RNI NO.- MPBIL/2020/79198

उद्घोष समय

वर्ष 05 अंक 82 | सतना,, गुरुवार 11 सितंबर,2025 | पृष्ठः 4, मूल्यः 1 रूपए

सीजेआई बीआर गवई ने कहा- हमें अपने संविधान पर गर्व होना चाहिए, नेपाल के हालात पर की अहम टिप्पणी

नई दिल्ली एजेंसी। नेपाल में पिछले दो दिनों से हो रहे उग्र प्रदर्शनों और राजनीतिक संकट पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बी।आई। गवई ने टिप्पणी की है। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट में प्रेसिडेंशियल रेफरेंस मामले की सुनवाई चल रही थी, जहां संविधान पीठ ने भारत के लोकतांत्रिक ढांचे और संविधान की मजबूती को लेकर अहम बातें कहीं। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ की अध्यक्षता कर रहे चीफ जस्टिस बी।आई। गवई ने कहा कि हमें अपने संविधान पर गर्व होना चाहिए। उन्होंने पड़ोसी देशों का जिक्र करते हुए कहा कि नेपाल की स्थिति सबके सामने है। इस पर जस्टिस विक्रम नाथ ने तुरंत कहा कि बांग्लादेश में भी इसी तरह की घटनाएं देखने को मिली हैं। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बहस में हिस्सा लेते हुए संविधान की ताकत को रेखांकित किया। उन्होंने आपातकाल का उदाहरण देते हुए कहा कि जब इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगाई, तब जनता ने ऐसा सबक सिखाया कि कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई और खुद इंदिरा गांधी को भी अपनी सीट गंवानी पड़ी। हालांकि, जब बाद की सरकार जनता को संभाल नहीं पाई तो उसी जनता ने इंदिरा गांधी को भारी बहुमत के साथ दोबारा सत्ता में लौटा दिया। इस पर चीफ जस्टिस गवई ने तुरंत जोड़ा कि वह भी प्रचंड बहुमत के साथ। इस पर सॉलिसिटर जनरल ने सहमति जताते हुए कहा कि यही हमारे संविधान की असली ताकत है और यह कोई राजनीतिक तर्क नहीं बल्कि सच्चाई है। उधर, नेपाल में बीते दो दिनों से भ्रष्टाचार और वंशवादी राजनीति के खिलाफ भड़के प्रदर्शनों ने हिंसक रूप ले लिया। हालात इतने बिगड़े कि प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और राष्टपति को इस्तीफा देना पड़ा।

नेपाल की कमान संभाल सकती हैं सुशीला कार्की

नई दिल्ली एजेंसी। नेपाल की पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की को कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। सोशल मीडिया पर प्रतिबंध और भ्रष्टाचार के खिलाफ हिंसक आंदोलन के बाद केपी शर्मा ओली प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे चुके हैं। सुशीला कार्की नेपाल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश रह चुकी हैं। अब उनसे उम्मीद की जा रही है कि वह इस संकट के समय में देश का नेतृत्व करेंगी, जब तक नए चुनाव नहीं हो जाते। आज सुबह जेन-जेड आंदोलन के सदस्यों की एक वर्चुअल बैठक में सुशीला कार्की का नाम सामने आया। कार्की का जन्म सात जून 1952 को विराटनगर में हुआ था। उन्होंने राजनीति शास्त्र और कानून की पढ़ाई की और उसके बाद वकालत और कानूनी सुधारों के क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की। सुप्रीम कोर्ट में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने कई ऐतिहासिक मामलों की सुनवाई की, जिनमें चुनावी विवाद भी शामिल थे। उनके फैसलों ने यह साबित किया कि न्यायपालिका लोकतंत्र की रक्षा करने वाली एक अहम संस्था है। नेपाल प्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, अंतरिम प्रधानमंत्री की नियुक्ति को लेकर एक बैठक में गंभीर चर्चा हुई। इस बैठक में पांच हजार से ज्यादा लोग शामिल हुए। इनमें सबसे ज्यादा लोगों ने नेपाल की पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की का समर्थन किया। काठमांडू महानगरपालिका के मेयर बालने शाह जेन-जेड पीढ़ी के बीच सबसे लोकप्रिय माने जाते हैं। लेकिन एक जेन-जेड प्रतिनिधि ने कहा कि अब वह (बालेन) हमारी बातों का जवाब नहीं दे रहे हैं। प्रतिनिधि ने कहा, जब उन्होंने फोन नहीं उठाया, तब अन्य नामों पर चर्चा शुरू हुई। सुशीला कार्की के नाम को सबसे ज्यादा समर्थन मिला। सुशीला कार्की को पहले ही जेन-जेड आंदोलनकारियों की ओर से कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनने का प्रस्ताव दिया जा चुका था। सूत्रों के अनुसार, उन्होंने इसके लिए 1,000 लिखित हस्ताक्षरों की मांग की थी। लेकिन उन्हें 2,500 से भी ज्यादा हस्ताक्षर दिए गए, जो उनकी मांग से कहीं ज्यादा थे।

12 सितंबर को उपराष्ट्पति का पद ग्रहण कर सकते हैं सीपी राधाकृष्णन, राष्ट्रपति मुर्मू दिलाएंगी शपथ

नई दिल्ली एजेंसी। देश के निर्वाचित उपराष्ट्पति सीपी राधाकृष्णन 12 सितंबर को पद की शपथ ले सकते हैं। अधिकारियों ने बताया कि राष्ट्पति द्रौपदी मुर्मू शुक्रवार को राधाकृष्णन को शपथ दिलाएंगी। राष्ट्पति भवन में 12 सितंबर को एक औपचारिक समारोह में शपथ ग्रहण संपन्न होगा। 67 वर्षीय राधाकृष्णन ने मंगलवार को हुए उपराष्ट्पति चुनाव में संयुक्त विपक्षी उम्मीदवार बी. सुदर्शन रेड्डी को हराकर जीत हासिल की थी। यह चुनाव तत्कालीन उपराष्ट्पति जगदीप धनखड़ के 21 जुलाई को अचानक दिए गए इस्तीफे के बाद कराया गया था। संसद भवन में मंगलवार को हुए मतदान में राधाकृष्णन को 752 वैध मतों में से प्रथम वरीयता के 452 वोट मिले थे, जबकि रेड्डी को प्रथम वरीयता के महज 300 वोट ही मिले थे। 14 सांसदों ने क्रॉस वोटिंग की। उपराष्ट्पति चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के सभी सांसद मतदाता होते हैं। देश में 17 बार उपराष्ट्पति पद का चुनाव हुआ जिसमें सर्वपल्ली राधाकृष्णन और हामिद अंसारी दो कार्यकाल तक इस पद पर रहे। निर्वाचन अधिकारी पीसी मोदी ने बताया, 781 मतदाताओं में से 98.2 फीसदी यानी 767 ने मतदान किया। इनमें 15 वोट अवैध पाए गए जिससे वैध मतों की संख्या 752 रह गई। वहीं एक डाक मत को रद्द घोषित कर दिया गया क्योंकि संबंधित सांसद ने वोट डालने से इन्कार किया है। उपराष्ट्पति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कुल 788 सदस्य होते हैं।

पीएम मित्रा पार्क से टेक्सटाइल सेक्टर में मध्यप्रदेश को मिलेगा नया आयाम : मुख्यमंत्री

कोलकाता इंटरैक्टिव सेशन में मिले 14,600 करोड़ के निवेश प्रस्ताव,प्रधानमंत्री के मेक इन इंडिया और विकसित भारत के संकल्प को करेंगे साकार

भोपाल एजेंसी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मध्यप्रदेश में उत्पादित आर्गेनिक कॉटन की मांग अनेक देशों में है। प्रदेश टेक्सटाइल का हब बनने की ओर अग्रसर है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने देश में 7 पीएम मित्रा पार्क स्वीकृत किये, उसमें से पहले पीएम मित्रा पार्क का भूमि-पूजन करने प्रधानमंत्री श्री मोदी 17 सितम्बर को धार जिले में आ रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने उद्योगपतियों का आहवान किया कि वे मध्यप्रदेश आये, राज्य सरकार निवेशकों को पीएम मित्रा पार्क में हर संभव सहायता और सुविधा उपलब्ध करवायेगी। धार का पीएम मित्रा पार्क भारत के औद्योगिक विकास की यात्रा में महत्वपूर्ण आयाम जोड़ेगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बुधवार को कोलकाता के.जे. डब्ल्यू मैरियट होटल में निवेश संभावनाओं पर इंटरैक्टिव सेशन को संबोधित कर रहे थे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने उद्योगपतियों के इंटरैक्टिव सेशन में मध्यप्रदेश को निवेश और औद्योगिक विकास के लिए सबसे भरोसेमंद और अवसरों से भरा राज्य बताया। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश की रणनीतिक भौगोलिक स्थिति, देश के मध्य में स्थित होने के कारण उत्तम कनेक्टिविटी, विश्वस्तरीय आधारभूत ढांचा और औद्योगिक शांति इसे उद्योगपतियों के लिए आदर्श निवेश स्थल बनाते हैं। उन्होंने कहा कि यह पार्क राज्य के टेक्सटाइल और गारमेंट सेक्टर को वैश्विक मानकों तक पहुंचाने के साथ रोजगार और आर्थिक विकास में नए आयाम खोलेगा।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश की शुद्ध और ऑर्गेनिक कॉटन उत्पादन क्षमता इसे टेक्सटाइल निवेश के लिए विशेष बनाती है। पीएम मित्रा पार्क के माध्यम से राज्य में उत्पादन और प्रोसेसिंग के उच्च मानक स्थापित होंगे, जिससे निवेशकों को लाभ के साथ रोजगार के अवसर भी सुनिश्चित होंगे। उन्होंने उद्योगपतियों को भरोसा दिलाया कि राज्य में निवेश स्थिर, पारदर्शी और सुरक्षित वातावरण में किया जा सकता है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने उद्योगपतियों का आहवान किया कि आइये हम संकल्प लें कि स्वदेशी अपनायेंगे, हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेंगे और प्रधानमंत्री श्री मोदी के %मेक इन इंडिया% और विकसित भारत के संकल्प को पूरी शक्ति के साथ साकार करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कोलकाता की समृद्ध सांस्कृतिक और बौद्धिक परंपरा का सम्मान करते हुए कहा कि स्वामी विवेकानंद, नेताजी सुभाषचंद्र बोस और रवींद्रनाथ टैगोर जैसे महापुरुषों ने देश को नई दिशा दी। उन्होंने कहा कि यह प्रेरक इतिहास और बौद्धिक परंपरा उद्योग जगत के लिए प्रेरक है और मध्यप्रदेश के औद्योगिक विकास और निवेश के दृष्टिकोण से साथ जुड़ती है। मुख्यमंत्री ने उद्योगपतियों से कहा कि कोलकाता जैसे ऐतिहासिक और बौद्धिक केंद्र से संवाद करना राज्य में निवेश के लिए उत्साह और नई ऊर्जा प्रदान करता है। उन्होंने बताया कि राज्य में विकसित औद्योगिक कॉरिडोर, लॉजिस्टिक हब और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर निवेशकों को मजबूत प्रतिस्पर्धी लाभ देते हैं। सड़क, रेल और हवाई नेटवर्क के माध्यम से पूरे देश में उत्पाद और सेवाओं की आपूर्ति सरल और त्वरित रूप से की जा सकती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में निवेशकों को सरल प्रक्रियाओं, सुलभ नीतियों और सक्रिय सरकारी सहयोग के माध्यम से व्यवसाय का विस्तार करने का पूर्ण अवसर मिलता है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मध्यप्रदेश की निवेश नीतियों पर जोर देते हुए कहा कि राज्य में उद्योगपतियों को हर प्रकार की सुविधा, सुगमता और सुरक्षा प्रदान की जाती है। उन्होंने कहा कि राज्य में औद्योगिक शांति सुनिश्चित है और किसी प्रकार की हड़ताल या व्यवधान के कारण निवेश प्रभावित नहीं होता। उन्होंने उद्योग जगत को भरोसा दिलाया कि मध्यप्रदेश में फैक्ट्री लगाना और संचालन करना सहज है, और राज्य के मध्य में होने के कारण पूरे देश में अपने उत्पाद और सेवाओं की आपूर्ति आसानी से की जा सकती है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने निवेशकों को बताया कि पीएम मित्रा पार्क के माध्यम से टेक्सटाइल और गारमेंट सेक्टर में राज्य की औद्योगिक क्षमता और रोजगार सृजन को नई ऊंचाइयों तक ले जाया जाएगा। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार की नीतियों का उद्देश्य किसानों, उद्योगपतियों और युवाओं को समान रूप से लाभ पहुंचाना है। राज्य में किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य और प्रोसेसिंग का सही अवसर मिलता है, उद्योगपतियों को व्यवसाय विस्तार की सुविधा है और युवाओं को रोजगार के अवसर सुनिश्चित किए जाते हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने उद्योग जगत को आमंत्रित करते हुए कहा कि मध्यप्रदेश में निवेश केवल व्यावसायिक विस्तार नहीं है, बल्कि सतत विकास और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में भागीदारी का अवसर है। उन्होंने उद्योगपतियों को भरोसा दिलाया कि पीएम मित्रा पार्क और अन्य औद्योगिक हब राज्य की टेक्सटाइल, गारमेंट और अन्य सेक्टरों में निवेशकों के लिए लाभकारी और सुरक्षित वातावरण प्रदान करते हैं।

अच्छी और कमजोर सीटों के बीच संतुलन जरूरी : कांग्रेस

नई दिल्ली एजेंसी। बिहार में महागठबंधन के दलों के बीच सीट बंटवारे को लेकर चल रही बातचीत के बीच कांग्रेस ने बुधवार को कहा कि सीटों का बंटवारा करते समय अच्छी और कमजोर सीटों में संतुलन बनाए रखना जरूरी है। साथ ही, अगर नए दल गठबंधन में शामिल होते हैं, तो मौजूदा सभी दलों को अपनी-अपनी सीटों में से कुछ सीटें छोड़नी होंगी। यह बयान उस समय आया है जब महागठबंधन में झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी (आरएलजेपी) को शामिल करने की चर्चा चल रही है।

कांग्रेस नेता और बिहार के प्रभारी कृष्णा अल्लावरु ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा और चुनाव आयोग की मिलीभगत से वोट चोरी की जा रही है। उन्होंने कहा, %पहले चुनाव आयुक्त की नियुक्ति प्रक्रिया बदली गई, मुख्य न्यायाधीश को हटा दिया गया और गृहमंत्री को शामिल किया गया। फिर कानून में बदलाव कर यह सुनिश्चित किया गया कि चुनाव आयुक्त के खिलाफ कोई कार्रवाई न हो सके। इसके बाद मतदाता सूची में हेराफेरी की गई और चुनाव के दिन गड़बड़ी की गई।कृष्णा अल्लावरु ने उदाहरण देते हुए कहा,वाराणसी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार कई राउंड तक आगे थे, लेकिन लाइव अपडेट अचानक रोक दिए गए और आखिरी समय में नरेंद्र मोदी को विजेता घोषित कर दिया गया।% उन्होंने कहा कि वोट चोरी करने वाली सरकार जनता की समस्याओं जैसे महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, अपराध और पेपर लीक की परवाह नहीं करती। वहीं बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सहयोगी दलों के बीच सीट बंटवारे पर उन्होंने कहा, %हर राज्य में कुछ सीटें अच्छी होती हैं, कुछ कमजोर। एक ही पार्टी को सिर्फ अच्छी सीटें और दूसरी पार्टी को कमजोर सीटें नहीं दी जानी चाहिए। हमारा प्रयास है कि सभी दलों को संतुलित हिस्सेदारी मिले।% उन्होंने साफ किया कि फिलहाल राहुल गांधी की अगुवाई में कोई नई यात्रा (यात्रा कार्यक्रम) निकालने की योजना नहीं है। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने बताया कि कांग्रेस की %वोटर अधिकार यात्रा से यह मुद्दा उठाया गया कि बिहार में विशेष मतदाता सूची संशोधन (एसआईआर) के दौरान पहचान के 11 दस्तावेजों में आधार कार्ड शामिल नहीं था।

जेनेवा में भारत का पलटवार, पाकिस्तान को बताया 'कूड़ा ढोने वाला ट्रक', स्विट्जरलैंड को भी फटकारा

जिनेवा एजेंसी । जिनेवा में संयुक्त राष्ट मानवाधिकार परिषद (यूएनएचआरसी) के 60वें सत्र की 5वीं बैठक में भारत ने पाकिस्तान और स्विट्जरलैंड को करारा जवाब दिया। भारतीय राजनयिक क्षितिज त्यागी ने अपने बयान में कहा कि भारत आतंकवाद से निपटने के लिए पूरी तरह सक्षम है और किसी से सीखने या सलाह लेने की जरूरत नहीं है।

क्षितिज त्यागी ने 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले का जिक्र करते हुए कहा, हमारे संतुलित और उचित जवाब ने यह साफ कर दिया है कि भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जाएगा। हम अपनी संप्रभुता से कोई समझौता नहीं करेंगे और आतंक को बढ़ावा देने वाले असफल देश के झूठे प्रचार को बार-बार उजागर करते रहेंगे। उन्होंने पाकिस्तान पर सीधा हमला करते हुए कहा कि उसका अस्तित्व ही आतंकवाद और झूठे प्रचार पर टिका है। हम फिर से मजबूर हैं कि उस देश की उकसावे की बातों का जवाब दें, जिसके नेता ने हाल ही में अपने देश की तुलना कूड़ा ढोने वाले ट्रक से की थी। यह तुलना सही बैठती है क्योंकि पाकिस्तान लगातार पुराने झूठ और बासी प्रोपेगेंडा इस मंच पर लेकर आता है। क्षितिज त्यागी ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन को भी अपने हित में इस्तेमाल करता है और भारत के खिलाफ उसकी बीमारी जैसी जुनूनी सोच उसके लिए अस्तित्व का सहारा बन गई है।स्विट्जरलैंड के बयान पर भी प्रतिक्रिया देते हुए त्यागी ने कहा कि भारत का घनिष्ठ मित्र होने के बावजूद, स्विट्जरलैंड ने गलत और सतही टिप्पणियां की हैं। यूएनएचआरसी के अध्यक्ष होने के नाते स्विट्जरलैंड को झूठे नैरेटिव फैलाने के बजाय अपने देश की समस्याओं, जैसे नस्लभेद, भेदभाव और विदेशियों के प्रति नफरत पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा और विविध लोकतंत्र है।

'वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के आरोपों पर सफाई दे चुनाव आयोग, हाई कोर्ट ने याचिका खारिज कर लगाया जुर्माना

नई दिल्ली एजेंसी। मद्रास हाईकोर्ट ने उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें याचिकाकर्ता ने चुनाव आयोग को निर्देश देने की मांग की थी कि वह 2024 के आम चुनावों में मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी के आरोपों पर स्पष्टीकरण दे। ये आरोप विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाई गई थी।

हाई कोर्ट ने आदेश में कहा, यह याचिका पूरी तरह से भ्रामक और आधारहीन है। अदालत ने साफ किया कि इसमें ठोस सामग्री का अभाव है। यह केवल कुछ मंचों पर लगाए गए आरोपों और प्रति-आरोपों पर आधारित है।

अदालत ने यह भी माना कि इस रूप में दायर याचिका अस्पष्ट है और इसमें पर्याप्त तथ्य व विवरण नहीं दिए गए हैं, इसलिए आयोग को अपना पक्ष स्पष्ट करने का निर्देश जारी नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने इस याचिका को खारिज करते हुए याचिकाकर्ता पर 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है , जिसे तमिलनाडु राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को जमा कराना होगा।

साथ ही अदालत ने यह स्पष्ट किया कि उसने इस मामले के मेरिट्स पर कोई राय नहीं दी है और चुनाव आयोग इन मुद्दों पर स्वतंत्र रूप से अपना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। अपनी अर्जी में याचिकाकर्ता ने कहा, अदालत को प्रतिवादी को निर्देश देना चाहिए कि वह इस अदालत के समक्ष सभी निर्वाचन क्षेत्रों के लिए प्रासंगिक मतदाता सूची डेटा को मशीन-पठनीय प्रारूप में प्रस्तुत करे और सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध कराए, साथ ही इन आरोपों के जवाब में किए गए सभी कार्यों, पूछताछ, ऑडिट और उपायों की विस्तृत स्थिति रिपोर्ट भी उपलब्ध कराए, ताकि पारदर्शिता, जनता का विश्वास और हमारे संविधान के अनुच्छेद 324, 14, 19 (1) (ए) के अनुसार स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के संवैधानिक जनादेश को बनाए रखा जा सके।

पीएम मोदी ने इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी से की बातचीत

यूक्रेन संघर्ष को लेकर हुई चर्चा

नई दिल्ली एजेंसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को अपनी इतालवी समकक्ष जॉर्जिया मेलोनी के साथ भारत और यूरोपीय संघ (ईयू) के बीच प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते पर चर्चा की और इसके समर्थन के लिए उनका आभार व्यक्त किया। फोन पर बातचीत में, मोदी ने मेलोनी के साथ यूक्रेन में संघर्ष को समाप्त करने के उपायों के साथ-साथ भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे (आईएमईईईसी) के कार्यान्वयन पर भी चर्चा की।

पीएम मोदी ने एक्स पर साझा की जानकारी पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा कि प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ अच्छी बातचीत हुई। हमने भारत-इटली रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करने की अपनी साझा प्रतिबद्धता दोहराई और यूक्रेन संघर्ष को जल्द समाप्त करने में साझा रुचि जताई है। भारत-यूरोपीय संघ के बीच आपसी हितों पर आधारित व्यापार समझौते को आगे बढ़ाने और आईएमईईईसी पहल के तहत कनेक्टिविटी को प्रोत्साहित करने में इटली के सक्रिय समर्थन के लिए प्रधानमंत्री मेलोनी का धन्यवाद किया। भारत और यूरोपीय संघ इस साल के अंत तक प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) को अंतिम रूप देने पर विचार कर रहे हैं। दोनों पक्ष इस सप्ताह नई दिल्ली में 13वें दौर की वार्ता कर रहे हैं। भारत और यूरोपीय संघ ने आठ वर्षों से अधिक के अंतराल के बाद जून 2022 में मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) के लिए वार्ता फिर से शुरू की। आईएमईईईसी पहल को 2023 में दिल्ली में आयोजित जी20 शिखर सम्मेलन के दौरान अंतिम रूप दिया गया।

नेपाल के बाद फ्रांस में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन

बजट कटौती के विरोध में 1 लाख लोग सड़क पर; 80 हजार पुलिसकर्मी तैनात, 300 उपद्रवी गिरफ्तार

नई दिल्ली एजेंसी। नेपाल में सोमवार और मंगलवार को सरकार के खिलाफ हुए आंदोलन की आग अभी ठंडी भी नहीं पड़ी थी कि दुनिया के एक और क्षेत्र में सरकारी नीतियों के खिलाफ प्रदर्शनों की शुरुआत हो गई है। इस बार विरोध का केंद्र है फ्रांस और निशाने पर है राष्टपति इमैनुएल मैक्रों की सरकार की नीतियां। हालांकि, नेपाल से उलट फ्रांस का प्रदर्शन सरकार के किसी अचानक लिए गए फैसले के बाद शुरू नहीं हुआ है, बल्कि इसे लेकर हलचल लंबे समय से जारी थी।

फ्रांस में 15 जुलाई को प्रधानमंत्री फ्रांस्वा बायरू ने राष्ट्रीय बजट पेश किया था। इसमें 2026 के लिए वित्तीय योजना में खर्चों को घटाने का जिक्र था। बायरू ने एलान किया था कि फ्रांस अपने बजट खर्च को 4.38 करोड़ यूरो (करीब 452 करोड़ रुपये) घटा रहा है। इसके जरिए सरकार अपने बढ़ते आर्थिक घाटे को कम करने की कोशिश को दर्शा रही थी। हालांकि, इस बजट कटौती के अलावा तीन ऐसी चीजों को खत्म करने की बात कही गई, जिसे फ्रांस के लोग मानने के लिए तैयार नहीं दिखे।

इधर फ्रांस में बायरू सरकार ने अपनी योजनाओं को आगे रखा, उधर सोशल मीडिया पर एक बड़ा तबका इनके खिलाफ आंदोलन की तैयारी करने लगा। देखते ही देखते पोस्ट्स में क्ष्म4ष्षहल्ल, स्तुह्यश्ड्डह्वह्यह्यड्डठुष्ड्ड द्गह्ल ह्यश्ड्यद्बस्त्रड्डह्लद्बह्लु वायरल हो गया, जिसका मतलब है %बहिष्कार, अवज्ञा और एकजुटता%। यहीं से फ्रांस में 10 सितंबर को राष्ट्रीय आंदोलन की नींव पड़ी। इन प्रदर्शनों को पहले ही- %ब्लॉक एवरीथिंग% नाम दे दिया गया। यानी इस दिन सरकार की नीतियों के विरोध में लोग सड़कों पर उतरकर शहरों को जहां-तहां रोक देंगे। इस प्रदर्शन को फिलहाल सिर्फ एक दिन के लिए सीमित रखा गया है। इन प्रदर्शनों की अगुवाई द सिटीजन कलेक्टिव नाम के संगठन की तरफ से की जा रही है, जिसमें करीब 20 आयोजनकर्ता जुड़े हैं। फ्रांस के अखबार ला परिसियन के मुताबिक, यह संगठन अपने आप को राजनीतिक दलों और अन्य व्यापार संगठनों से स्वतंत्र बताता है। फ्रांस में जैसे-जैसे 10 सितंबर को होने वाली प्रदर्शनों का समर्थन बढ़ा, वैसे ही सरकार को आम लोगों के गुस्से का अंदाजा भी होने लगा। इस स्थिति के मद्देनजर अगस्त के आखिरी हफ्तों में प्रधानमंत्री बायरू ने संसद में सरकार और बजट को लेकर विश्वास मत लाने की बात कह दी। बायरू का मकसद था कि सरकार अगर इस बजट को पारित करा लेती है तो इसका मतलब होगा कि फ्रांस में खर्चों में कटौती को जन प्रतिनिधियों का समर्थन है। हालांकि, अगर यह पारित नहीं होता तो वे इस्तीफा दे देंगे।

दिल में घुसा तीर, एक की मौत, एक दर्जन से अधिक घायल, जमीन को लेकर भिड़े 300 लोग

गुना एजेंसी। मध्य प्रदेश के गुना जिले के छिकारी-चाकरी इलाके में वन भूमि पर कब्जे को लेकर बड़ा बवाल हो गया। मंगलवार को दो पक्षों के बीच हुए इस विवाद में पत्थर, हथियार, गोफान और तीर कमान चले। इस दौरान एक दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए, जबकि एक की सीने में तीर लगने से मौत हो गई। विवाद की सूचना पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और हालात काबू करने की कोशिश की। इसके बाद भी पुलिस को मृतक का शव घर बाहर निकालने में 16 घंटे से अधिक का समय लग गया। बुधवार को शव को पोस्टमार्टम के लिए बमोरी अस्पताल भेजा गया। विवाद के बाद गांव में तनाव के हालात हैं, इसे देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है।

जानकारी के अनुसार, जिले के बमौरी क्षेत्र के चाकरी गांव में भील और भिलाला समाज के बीच लंबे समय से वन भूमि पर कब्जे को लेकर विवाद चल रहा है। जिसे निपटाने के लिए मंगलवार को समाज की पंचायत बुलाई गई थी। पंचायत में दोनों ही पक्षों ने जमीन पर अपना-अपना दावा पेश किया। कोई भी पक्ष जमीन पर कब्जा छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। ऐसे में पंचायत में कोई फैसला नहीं हो सका। लेकिन, बातचीत के दौरान दोनों पक्षों के लोग भिड़ गए। देखते ही देखते 300-400 लोग आमने-सामने आ गए और एक-दूसरे पर पथराव शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने तीर कमान, गोफन और हथियारों का इस्तेमाल किया। झगड़े में एक दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। इस दौरान सीने में तीर लगने से चाकरी में रहने वाले गंगाराम भील (55) की मौत हो गई।

विवाद की सूचना पर एसडीएम, तहसीलदार, एसडीओपी समेत बड़ी संख्या में पुलिस बल गांव में पहुंचा। लेकिन, ग्रामीणों ने पुलिस और प्रशासनिक टीम को गांव में प्रवेश नहीं करने दिया। रातभर पुलिस की टीम गांव के बाहर रही और हालात काबू करने के प्रयास किए। बुधवार को गांव के प्रमुख लोगों से बातचीत के बाद पुलिस ने अंदर प्रवेश किया और शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा। कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल ने बताया कि विवाद फतेहगढ़ और बमौरी के सेंटर पॉइंट पर हुआ है, जहां करीब 60 हेक्टेयर फॉरेस्ट जमीन पर भिलाला समाज खेती कर रहा था। इस जमीन पर भील समाज भी अपना हक जता रहा है। इसी को लेकर दोनों समुदायों में विवाद हो गया। विवाद के बाद गांव के हालात को लेकर अधिकारियों ने बताया कि स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन तनाव बरकरार है। एक व्यक्ति की मौत भी हो गई है। पुलिस और प्रशासन की टीम गांव में मौजूद है। कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल ने कहा कि हमारी पूरी टीम और पुलिस फोर्स मौके पर है।

जिला सिवनी को अटल पेंशन योजना में उत्कृष्ट कार्यप्रदर्शन हेतु देश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ

अटल-पेंशन आउटरीच कार्यक्रम का हुआ आयोजन

कैलाश लाहोरी उद्घोष समय जिला ब्यूरो सिवनी

सिवनी / जिला सिवनी को अटल पेंशन योजना में उत्कृष्ट कार्यप्रदर्शन हेतु देश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। इसी क्रम में आज अटल पेंशन आउटरीच कार्यक्रम का आयोजन कलेक?टर सुश्री संस्कृति जैन के निर्देशन में किया गया।

कार्यक्रम में नई दिल्ली से भारतीय पेंशन निधि नियामक एवं विकास प्राधिकरण के उप महाप्रबंधक श्री सुधीर सिंह एवं प्रबंधक श्री निशांत आनंद विशेष रूप से उपस्थित रहे। गौरतलब है कि दिनांक 24 अगस्त 2025 को क्क्रत्रक्र द्वारा सिवनी जिले के अग्रणी जिला प्रबंधक श्री प्रवीण कुमार दिसोरिया को सम्मानित किया गया था।

जिले के उत्कृष्ट प्रदर्शन को देखते हुए ही क्क्रत्रक्र के वरिष्ठ अधिकारियों ने कार्यक्रम में उपस्थिति दर्ज की। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में कलेक?टर सुश्री संस्कृति जैन, भारतीय स्टेट बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक श्री आनंद कुमार, सेंट्रल बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक श्री कुमार उत्कर्ष सहित विभिन्न बैंकों एवं विभागों के अधिकारीगण उपस्थित रहे। इस अवसर पर लीड बैंक अधिकारी ने मिशन जीवन पर्यंत की सफलता पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि इस उपलब्धि और सम्मान का श्रेय कलेक्टर सुश्री संस्कृति जैन एवं समस्त बैंकिंग संस्थानों तथा विभागीय अधिकारियों को जाता है।

सिवनी जिलास्तरीय जनसुनवाई में प्राप्त हुए 171 आवेदन

कैलाश लाहोरी उद्घोष समय जिला ब्यूरो सिवनी

सिवनी / प्रत्येक मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित होने वाली जिलास्तरीय जनसुनवाई कलेक्टर सुश्री संस्कृति जैन की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। जनसुनवाई में सीईओ जिला पंचायत श्री नवजीवन विजय सहित सभी विभागों के प्रमुख उपस्थित रहे। इस दौरान कलेक्टर सुश्री संस्कृति जैन द्वारा आमजन से प्राप्त विभिन्न शिकायतों एवं आवेदनों की गंभीरता से सुनवाई की गई तथा संबंधित अधिकारियों को त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निराकरण के निर्देश दिए गए। कलेक्टर सुश्री जैन ने कहा कि प्रत्येक प्रकरण का समाधान समय-सीमा में सुनिश्चित किया जाए ताकि आम नागरिकों को शीघ्र राहत मिल सके।

जिलास्तरीय जनसुनवाई में तहसील सिवनी अंतर्गत ग्राम कान्हीवाडा निवासी जुबेदा बी द्वारा भूमि का सीमांकन कराये जाने विषयक, तहसील कुरई अंतर्गत ग्राम पीपरवानी निवासी संतोष ठाकरे द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाये जाने विषयक, ग्राम जमुनिया थाना बंडोल निवासी रितेश पुसू द्वारा जंगली जंतुओं द्वारा नष्ट हुई फसल का मुआवजा दिलाये जाने विषयक, तहसील छपारा अंतर्गत संजय कालोनी छपारा निवासी आबिद खान द्वारा सुलभ शौचालय की राशि दिलाये जाने विषयक, केवलारी निवासी मनीराम नागोत्रा द्वारा निराश्रित पेंशन दिलाये जाने विषयक, ग्राम चुरनाटोला इंदावाडी सिवनी निवासी धानू मरकाम द्वारा वृद्धापेंशन दिलाये जाने एवं आधार कार्ड अपडेट कराये जाने विषयक, ग्राम विजयपानी सिवनी निवासी फिरदोस खान द्वारा मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना अंतर्गत राशि दिलाये जाने विषयक, ग्राम समनापुर केवलारी निवासी कृष्ण कुमार डेहरिया द्वारा विद्युत ट्रांसफार्मर लगाये जाने विषयक, इंदिरावार्ड केवलारी निवासी संतकुमार यादव द्वारा मुख्यमंत्री संबल योजना का लाभ दिलाये जाने विषयक,

ग्राम सिल्लोर कुरई निवासी संजय मरकाम द्वारा ग्राम कोहका में विद्युत प्रदाय किये जाने विषयक, ग्राम बदलापुर कुरई निवासी कंचन सिंह कहार द्वारा अवैध अतिक्रमण को हटाये जाने विषयक, ग्राम मेहलोन सिवनी निवासी झनकलाल धुर्वे द्वारा मुआवजा राशि दिलाये जाने विषयक, ग्राम पाटन लखनादौन निवासी तीरथ प्रसाद भलावी एवं अन्य द्वारा ग्राम में शमशान घाट निर्माण कराये जाने विषयक, ग्राम बिछुआ सिवनी निवासी शिवशंकर डहेरिया द्वारा पात्रता पर्ची दिलाये जाने विषयक, तहसील घंसौर अंतर्गत ग्राम बीजासेन निवासी कमलेश गिरी गोस्वामी द्वारा भूमि की ऋष्ण पुस्तिका दिलाये जाने विषयक, सिवनी निवासी साधना मरकाम द्वारा आवास योजना का लाभ दिलाये जाने विषयक, ग्राम ढाना हथनापुर सिवनी निवासी सवेरी लोधी द्वारा लाडली बहना योजना का लाभ दिलाये जाने विषयक सहित कुल 171 आवेदन प्राप्त हुए। प्राप्त आवेदनों पर नियमानुसार कार्यवाही कर शीघ्र निराकरण करने के निर्देश कलेक्टर सुश्री संस्कृति जैन ने संबंधित विभागाधिकारियों को दिए।

दिव्यांगजनों हेतु 7 दिवसीय विशेष प्रशिक्षण शिविर

कैलाश लाहोरी उद्घोष समय जिला ब्यूरो सिवनी

सिवनी / कलेक्टर सुश्री संस्कृति जैन के निर्देशन में आरसेटी द्वारा जिले के दिव्यांगजनों हेतु 7 दिवसीय विशेष प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ किया गया। इस प्रशिक्षण शिविर में दिव्यांगजनों को %शॉप कीपर% से संबंधित व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है, ताकि वे भविष्य में स्वरोजगार स्थापित कर आत्मनिर्भर बन सकें। श्री संदीप परते, प्रभारी उपसंचालक, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण सिवनी द्वारा बताया गया कि इस प्रकार के प्रशिक्षण शिविरों का मुख्य उद्देश्य दिव्यांगजनों को कौशल आधारित शिक्षा देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। ÷शॉपकीपर÷ का प्रशिक्षण दिव्यांगजनों को रोजगार की मुख्यधारा से जोड़ने में अत्यंत सहायक सिद्ध होगा।

इस अवसर पर श्रीमती पूजा शर्मा ने उपस्थित दिव्यांगजनों को संबोधित कर कहा कि आरसेटी समय-समय पर विभिन्न ट्रेड जैसे सिलाई-कढ़ाई, कंप्यूटर प्रशिक्षण, डेयरी, ब्यूटी पार्लर, कृषि कार्य, मोबाइल रिपेयरिंग आदि में भी प्रशिक्षण आयोजित करता है। इन प्रशिक्षणों के उपरांत प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र प्रदान किए जाते हैं, जो उनके लिए भविष्य में नौकरी प्राप्त करने या स्वयं का व्यवसाय शुरू करने में सहायक होते हैं। आरसेटी द्वारा प्रशिक्षण पूर्ण करने वाले प्रतिभागियों को स्वरोजगार हेतु बैंकों के माध्यम से कम ब्याज दर पर ऋष्ण सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। इस सुविधा से दिव्यांगजन आर्थिक रूप से मजबूत होकर समाज में आत्मसम्मान के साथ खड़े हो सकते हैं।

मठ स्कूल में संकल्प हब फॉर एंपॉवरमेंट ऑफ वूमेन अंतर्गत किशोरी बालिकाओं की एनीमिया एवं स्वास्थ्य जांच शिविर संपन्न

दिशा भृमण सिवनी । प्रशासक वन स्टॉप सेंटर महिला एवं बाल विकास विभाग सिवनी ने जानकारी देकर बताया कि कलेक्टर सुश्री संस्कृति जैन के निर्देशानुसार एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी मनोज लारोकर के मार्गदर्शन में संकल्प हब फॉर एंपॉवरमेंट ऑफ वूमेन के अंतर्गत 10 दिवसीय विशेष जागरुकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है।इसी क्रम में प्रशासक वन स्टॉप सेंटर सुश्री ईशा बाल्मिक के मार्गदर्शन में महिला बाल विकास विभाग स्वास्थ्य विभाग एवं शिक्षा विभाग के संयुक्त समन्वय से बुधवार 10 सितम्बर को शासकीय कन्या उच्चतम माध्यमिक शाला मठ स्कूल सिवनी में किशोरी बालिकाओं की एनीमिया जांच, स्वास्थ्य जांच एवं पोषण व्यंजन प्रदर्शनी का आयोजन किया गया जिसमें विद्यालय की कक्षा 9 से 12 तक की कुल 100 छात्राओं की स्वास्थ्य जांच कराई गई। आयोजन में महिला बाल विकास विभाग से श्रीमती चंद्रकांता भलावी महिला पर्यवेक्षक, श्रीमती कविता दुबे महिला पर्यवेक्षक एवं सुश्री आकांक्षा सोनी वन स्टॉप सेंटर, स्वास्थ्य विभाग से डॉ. श्री तारेंद्र डहरिया, डॉ. श्रीमती मयूरी अवधिया एवं शिक्षा विभाग से श्रीमती आभा सिंह प्राचार्य मठ स्कूल, श्रीमती लक्ष्मी चक्रवर्ती उ.म. शिक्षक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका उपस्थित रहे।

जिले में उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता

दिशा भृमण सिवनी । जिले में किसानों को यूरिया एवं अन्य उर्वरकों की आपूर्ति सुचारू रूप से की जा रही है। कलेक्टर सिवनी एवं उपसंचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास द्वारा प्रतिदिन भंडारण एवं वितरण की समीक्षा की जा रही है। जिले की 57 सहकारी समितियों में यूरिया 1489 मी.टन, डीएपी 747 मी.टन, एनपीके 441 मी.टन, एमओपी 205 मी.टन एवं एसएसपी 1450 मी.टन उपलब्ध है। इसी प्रकार डबल लॉक केन्द्रों में यूरिया 1675 मी.टन, डीएपी 2405 मी.टन, एनपीके 590 मी.टन, एमओपी 175 मी.टन तथा एसएसपी 568 मी.टन भंडारित है। जिला मार्केटिंग सोसायटी के पास यूरिया 60 मी.टन, डीएपी 115 मी.टन एवं एसएसपी 41 मी.टन उपलब्ध है। वहीं निजी फुटकर विक्रेताओं के पास यूरिया 968 मी.टन, डीएपी 823 मी.टन, एनपीके 467 मी.टन, एमओपी 123 मी.टन एवं एसएसपी 2334 मी.टन का भंडार है।उपसंचालक कृषि ने बताया कि सभी केन्द्रों से उर्वरक विक्रय सुचारू रूप से प्रारंभ है। उन्होंने कृषक भाइयों से अपील की है कि वे आवश्यकता अनुसार ही संतुलित मात्रा में उर्वरकों का उपयोग करें।

बिना हेलमेट और सीट बेल्ट जिला कार्यालय आने वालों को लौटाया गया वापस

सीटबेल्ट एवं हेलमेट पहनने के लिए जिला प्रशासन हुआ सख्त**

उद्घोष न्यूज़ नारायण प्रधान

जशपुरनगर । सड़क सुरक्षा को लेकर कलेक्टर रोहित व्यास ने सख्त रवैया दिखाते हुए बुधवार को जिला कार्यालय में नियमों के पालन को लेकर कार्रवाई की गई। जहां जिला कार्यालय में बिना हेलमेट और सीटबेल्ट के आने वाले सभी अधिकारियों, कर्मचारियों एवं कार्य हेतु आने वाले नागरिकों को दुपहिया वाहनों में हेलमेट एवं चार पहिया वाहनों में सीटबेल्ट लगाने की समझाइश देकर वापस लौटा गया। इस मौके पर जिला सेनानी नगर सेना विपिन किशोर लकड़ा ने भी जिला कार्यालय के मुख्य द्वार पर खड़े होकर लोगों को समझाइश दी।

उल्लेखनीय है कि कलेक्टर रोहित व्यास के द्वारा सड़क सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जिसके लिए उन्होंने सड़क सुरक्षा समिति की बैठक एवं समय सीमा बैठक में समस्त विभाग प्रमुखों तथा अधिकारियों को अपने कार्यालयों में कर्मचारियों को बिना हेलमेट एवं सीट बेल्ट के प्रवेश ना देने को निर्देश दिया गया है। आज प्रथम दिवस पर समझाइश देकर लोगों को हेलमेट पहनने को प्रेरित किया गया है पर आगामी दिनों में लगातार जांच कर लाइसेंस, गाड़ी के कागजात, हेलमेट, सीटबेल्ट, इंश्योरेंस आदि ना होने पर नियमानुसार जुर्माना लगाने का कार्यवाही भी की जाएगी। कलेक्टर ने विभाग प्रमुखों को भी सभी को प्रेरित करने के लिए सर्वप्रथम स्वयं सड़क सुरक्षा मानकों का पालन कर सीटबेल्ट एवं हेलमेट का अनिवार्य रूप से प्रयोग करने को कहा है।

स्कूटी पर गांजा तस्करी करते दो युवक गिरफ्तार, 4 किलो गांजा और वाहन जब्त

संवाददाता शाहनवाज़ खान जिला ब्यूरो रायगढ़

रायगढ़, 10 सितंबर । एसपी श्री दिव्यांग पटेल के मार्गदर्शन पर पुसौर पुलिस ने गांजा तस्करी पर बड़ी कार्रवाई करते हुए दो युवकों को स्कूटी पर गांजा लेकर ग्राहकों का इंतजार करते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों से 4 किलो गांजा और स्कूटी वाहन बरामद किया है, जिसकी कुल कीमत करीब 90 हजार रुपये आंकी गई है।

कार्यवाही पुसौर थाना क्षेत्र अंतर्गत की गई है, जहां थाना प्रभारी निरीक्षक रामकिंकर यादव को सूचना मिली थी कि ग्राम औरदा और जकेला के बीच स्थित मंदिर के पास दो युवक स्कूटी पर गांजा रखकर ग्राहक की तलाश में खड़े हैं। सूचना पर तत्काल एएसआई मनमोहन बैरागी और हमराह स्टाफ ने घेराबंदी कर छापेमारी की। पुलिस की कार्रवाई के दौरान मौके पर खड़े दो युवक भागने का प्रयास करने लगे, जिन्हें घेरकर पकड़ा गया। पूछताछ में उनकी पहचान रौनक अग्रवाल पिता वासु अग्रवाल उम्र 25 वर्ष निवासी रामभांठा वार्ड क्रमांक 03 थाना कोतवाली रायगढ़ और सोनू अहमद पिता खुरशीद अहमद उम्र 24 वर्ष निवासी फतेहाबाद हरियाणा हाल मुकाम पतरापाली थाना कोतरारोड़ रायगढ़ के रूप में हुई। संदेहियों की तलाशी लेने पर उनके कब्जे से दो पैकेट गांजा बरामद हुआ, जिनमें प्रत्येक का वजन 2 किलो यानी कुल 4 किलो मादक पदार्थ गांजा था, जिसकी अनुमानित कीमत 40 हजार रुपये है। साथ ही आरोपियों के पास से स्कूटी वाहन क्रमांक सीजी 13 एएफ 0615 जिसकी कीमत करीब 50 हजार रुपये है, को भी जब्त किया गया। आरोपियों के विरुद्ध थाना पुसौर में अपराध क्रमांक 247/2025 धारा 20(बी) एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया गया है।

कार्रवाई पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल के दिशा-निर्देशन और एडिशनल एसपी आकाश मरकाम, नगर पुलिस अधीक्षक मयंक मिश्रा के मार्गदर्शन में की गई, जिसमें थाना प्रभारी निरीक्षक रामकिंकर यादव, एएसआई मनमोहन बैरागी, उमाशंकर नायक, आरक्षक दिनेश गोंड, दिलीप सिदार, ठंडाराम गुप्ता, किर्तन यादव और विजय कुशवाहा की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

महिलाओं और बच्चियों के साथ छेड़खानी मामले में टेडुआ ग्राम सभा के लोग सी ओ चुनार को पत्रक सौंपा

अदलहाट, मीरजापुर। अदलहाट थाना क्षेत्र अंतर्गत टेडुआ

ग्राम सभा में दिनांक 7.9.2025 को ग्रामीणों के बीच हुए विवाद मामले में जिन लोगों के बीच मारपीट हुआ उन्हें ग्राम प्रधान द्वारा पंचायत बुलाकर मामला सलटाने की कोशिश किए जाने पर मारपीट की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, जिसमें सिविल ड्रेस में आए पुलिस वालों द्वारा महिलाओं को मारा - पीटा गया और उनके साथ बत्तमीजी किया गया। महिलाओं को काफ़ी चोटें आई हैं। तब से पूरे गांव में डर का माहौल बना हुआ था काफी महिलाएं - बच्चे और बच्चियां डरी हुई थीं। महिलाएं थाना पर जाने से डर रही थीं। जब सोशल मीडिया पर यह बात वायरल हुआ तो सरदार सेना के जिला अध्यक्ष ने ग्रामीणों से आकर उनका हाल जाना और घटना के बारे में जानकारी किया। तब 10 9.2025 को ग्राम सभा टेडुआ में सी ओ चुनार मंजरी राव जी और थाना प्रभारी अदलहाट इंस्पेक्टर अमित मिश्रा और सरदार सेना के तमाम कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी लोग पहुंच करके ग्रामीणों से बातचीत किए। उपरोक्त घटना के कारण ग्रामीणों में काफी आक्रोश बना हुआ हथा और लोग कप्तान से मिलने के लिए अड़े हुए थे और बार-बार जिद कर रहे थे कि हम लोग कप्तान साहब से अपनी बात बताएंगे। काफी समझने के बाद और सी ओ साहिबा के आश्वासन देने के कि दोषियों के साथ उचित कार्रवाई होगी। मैं स्वयं आप लोगों की बात कप्तान साहब तक पहुंचाऊंगी। सी ओ मंजरी राव ने ग्रामीणों द्वारा लिखा हुआ प्रार्थना पत्र लिया और पूरा आश्वसन दिया कि अब लड़कियों, महिलाओं पर कोई आपत्ति जनक टिप्पडी नही होगी। उन्होंने तत्काल पिकेट लगाने का आदेश दिया। जो आए दिन बच्चियों के साथ सड़क पर बदतमीजी और छींटाकसी जैसा वारदात किया जाता है, कुछ सोहदो द्वारा छेड़खानी किया जाता है, बच्चियो के साथ कोई बत्तमीजी मुझे बर्दाश्त नहीं होगी। लेकिन अभी भी ग्राम सभा टेडुआ में कहीं न कहीं भय का माहौल बना हुआ है, क्योंकि वहां के लोग पुलिसिया कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हैं। इस घटना में पुलिस द्वारा जिस तरह से कार्यवाही किया हर रहा है उन्हें कहीं न कहीं थाना अदलहाट की भूमिका संदिग्ध नजर आ रही है। अदलहाट थाना द्वारा ग्राम प्रधान टेडुआ के दबाव में फर्जी तरीके से 50 लोगों के ऊपर मुकदमा भी दर्ज कराया गया है, जिससे ग्रामीणों में काफ़ी आक्रोश है। ग्रामीणों ने थाना प्रभारी को हटाने का मांग भी किया है। फिलहाल सी ओ ने तत्काल कार्यवाही का आश्वासन देकर और प्रार्थना पत्र लेकर के चली गई। ग्राम सभा के लोग शांति व्यवस्था बनाए हुए हैं। लेकिन अगर उचित कार्रवाई नहीं होती है तो ग्रामीणों का कहना है कि हम आगे जाकर के उच्च अधिकारी के समक्ष अपनी बात रखेंगे। उक्त मौके पर

सरदार सेना के भी कुछ पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता

जिला अध्यक्ष सुनील पटेल फौजी, मुन्ना मैनेजर, विधानसभा प्रभारी विशाल सिंह, ऋषि, विधानसभा अध्यक्ष दयाशंकर सिंह, जिला उपाध्यक्ष संतोष यादव, विनय पटेल, सुशील पटेल, अभिषेक पटेल, इस्लाम भाई, गौरव, प्रिंस, चंद्रशेखर यादव, नंदलाल पटेल, मोनू पटेल और तमाम ग्रामीण उपस्थित रहे।

*बड़ी सौगातः- ग्रामीणों की वर्षों मांग हुई पूरी, मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने दी मंजूरी, बगीचा रेंगले मार्ग पर राजपुरी नाला में बनेगा उच्च स्तरीय पुल, 9 करोड़ 15 लाख की लागत किया जाएगा निर्माण, क्षेत्र वासियों ने मुख्यमंत्री का जताया आभार....

उद्घोष न्यूज़ नारायण प्रधान

जशपुरनगर 10 सितम्बर 2025/ मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर जिले में तेजी से विकास किया जा रहा है,वर्षों पुरानी ग्रामीणों की बहुप्रतीक्षित मांग विष्णुदेव साय की सरकार ने पूरा कर दिया है।छत्तीसगढ़ शासन ने जशपुर जिले के बगीचा से रेगले मार्ग पर राजपुरी नाला पर उच्च स्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण के लिए 9 करोड़ 15 लाख 14 हजार रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान कर दी है। वित्त विभाग की सहमति के बाद लोक निर्माण विभाग मंत्रालय, महानदी भवन नवा रायपुर से आदेश जारी किया गया है।आदेशानुसार पुल निर्माण की निविदा केवल 90 प्रतिशत बाधा रहित भूमि उपलब्ध होने के बाद ही आमंत्रित की जाएगी। साथ ही कार्य की तकनीकी स्वीकृति सक्षम अधिकारी से प्राप्त करना अनिवार्य होगा। शासन ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि निर्माण कार्य पूर्ण पारदर्शिता, मितव्ययिता और उच्च गुणवत्ता के साथ पूरा किया जाए।यदि निविदा दर 10 प्रतिशत से अधिक होगी अथवा अतिरिक्त कार्य जुड़ेंगे तो पुनः प्रशासकीय स्वीकृति लेना आवश्यक होगा। साथ ही कार्य की गुणवत्ता में किसी भी स्तर पर कमी पाए जाने पर जिम्मेदारी तय कर सख्त कार्रवाई की जाएगी।गौरतलब है कि इस पुल की मांग लंबे समय से की जा रही थी, क्योंकि बरसात के दिनों में राजपुरी नाला उफान पर आने से बगीचा-रेगले मार्ग पर यातायात प्रभावित हो जाता था। पुल बनने के बाद अब स्थानीय लोगों को निर्बाध आवाजाही की सुविधा मिलेगी।ग्रामीणों ने बताया कि साय सरकार ने जो वादा किया था उसे पूरा कर दिया है।सौगात मिलने के बाद क्षेत्र वासियों ने मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय का आभार जताया है।

धूमधाम एवं भक्तिमय भाव से दी गई विघ्नहर्ता को विदाई

उद्घोष समय सतना, अंकित शर्मा

सतना शहर के प्रतिष्ठित महाविद्यालय श्री रामाकृष्णा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, साइंस एंड मैनेजमेंट, करही, सतना में भगवान श्री गणेश जी दिनांक 27.08.2025 को विराजमान हुए थे। पूर्ण 11 दिन महाविद्यालय के छात्र/छात्राओं एवं स्टाफ मेम्बर्स के पूजन, अर्चन, वंदन एवं प्रत्येक दिन सांस्कतिक प्रस्तुतियां दी गई। 06.09.2025 को भगवान का हवन एवं महाप्रसाद वितरण कार्यक्रम किया गया। तदोपरांत भगवान के विसर्जन का कार्यक्रम किया गया। इस अवसर पर संस्था के चेयरमैन श्री शम्मी पुरी, श्री रामा कृष्णा ग्रुप डायरेक्टर श्री शाश्वत पुरी, टेक्निकल विंग डायरेक्टर डॉ. अग्निवेश अग्निहोत्री, एकेडमिक डायरेक्टर सुश्री शुभी खरे, फर्स्ट ईयर डीन श्री अभय मिश्रा, हायर सेमेस्टर डीन श्री दीपेश निगम, फार्मेसी डीन डॉ. अमित पाण्डेय, समस्त विभागाध्यक्ष, स्टाफ मेंबर्स एवं बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं मौजूद रहे।

मुख्यमंत्री ने दी बड़ी सौगात, कुनकुरी में बनेगा अत्याधुनिक इंटीग्रेटेड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, 63 करोड़ 84 लाख की मिली मंजूरी...

उद्घोष न्यूज़ नारायण प्रधान

जशपुरनगर 10 सितंबर 2025/ मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की दूरदर्शी सोच और नेतृत्व में जशपुर जिले को लगातार विकास की नई सौगात मिल रही हैं। खेल प्रतिभाओं को पहचान और बेहतर अवसर दिलाने की दिशा में प्रदेश सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाया है।जिले के कुनकुरी में अत्याधुनिक इंटीग्रेटेड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए शासन द्वारा 63 करोड़ 84 लाख 89 हजार रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है।यह खेल कॉम्प्लेक्स न केवल जशपुर बल्कि पूरे सरगुजा संभाग के लिए मील का पत्थर साबित होगा।खिलाड़ियों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधा इस कॉम्प्लेक्स के निर्माण से ग्रामीण और आदिवासी अंचल के युवाओं को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल सुविधाएं उपलब्ध होंगी।अब खिलाड़ियों को बड़े शहरों का रुख करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।यहीं पर उन्हें प्रशिक्षण, प्रतियोगिताएं और खेल आयोजन की बेहतर व्यवस्था मिलेगी।

ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों की छुपी हुई खेल प्रतिभाएं निखरकर सामने आएंगी।युवाओं के लिए खेलों में करियर और रोजगार की नई संभावनाएं भी खुलेंगी।स्थानीय खेल प्रेमियों और युवाओं ने मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय का आभार जताते हुए कहा कि इस कॉम्प्लेक्स के बनने से जशपुर जिले की पहचान खेलों के क्षेत्र में और भी मजबूत होगी।

ये होंगी विशेष सुविधाएंइंटीग्रेटेड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को अत्याधुनिक खेल ढांचे और सुविधाओं से सुसज्जित किया जाएगा। इसमें शामिल होंगे एथलेटिक्स ट्रैक एवं पवेलियन,बास्केटबॉल कोर्ट कबड्डी और खो-खो के मैदान,आधुनिक स्विमिंग पूल एवं ड्रेस चेंजिंग रूम,वॉलीबॉल ग्राउंड ,जंपिंग गेम,और खेल उपकरण इन सभी व्यवस्थाओं से खिलाड़ियों को बड़े स्तर पर प्रशिक्षण और प्रतियोगिता का अनुभव मिलेगा।

जशपुर का खेलों में नया स्वर्णिम अध्याय

जशपुर जिला पहले से ही अपनी खेल प्रतिभाओं के लिए प्रसिद्ध रहा है। यहां से कई खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचे हैं। अब इस इंटीग्रेटेड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के निर्माण से यह परंपरा और मजबूत होगी।मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय का यह कदम न केवल खेल प्रतिभाओं के उज्ज्वल भविष्य की गारंटी है, बल्कि यह जशपुर को खेलों की भूमि के रूप में नई पहचान भी दिलाएगा।

भारतीय सेना के अधिकारी बने- आभाष रहांगडाले

IIT पैकेज ठुकराकर चुनी देशसेवा की राह

कैलाश लाहोरी उद्घोष समय जिला ब्यूरो सिवनी

सिवनी / सिवनी जिले का नाम आज गर्व से गूंज रहा है। जिले के युवा आभाष रहांगडाले ने सातवें प्रयास में भारतीय सेना में अधिकारी (लेफ्टिनेंट) बनकर असाधारण उपलब्धि हासिल की है। 6 सितम्बर को ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकैडमी (ह्ळ्ञ), गया से कठोर सैन्य प्रशिक्षण पूरा करने के बाद उन्हें भारतीय सेना में राजपत्रित अधिकारी के रूप में कमीशन प्राप्त हुआ। यह सफलता न सिर्फ उनके परिवार के लिए, बल्कि पूरे जिले के लिए सम्मान का विषय है।

शिक्षा से सेवा तक का सफर

आभाष ने अपनी स्नातक की पढ़ाई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (हृद्धञ्ज), भोपाल से की। इसके बाद द्वञ्ञ्श परीक्षा में 291वीं रैंक प्राप्त कर द्धद्धञ्ज खड़गपुर में रूञ्जद्गष्द्ध में प्रवेश लिया। यहां उन्हें ?16 लाख वार्षिक का पैकेज भी ऑफर हुआ, मगर उनका मन कॉर्पोरेट करियर में नहीं, बल्कि देश सेवा की वर्दी में था। उन्होंने आराम और सुविधाओं से भरे जीवन को ठुकराकर भारतीय सेना का कठिन रास्ता चुना।

6 बार असफलता, सातवें प्रयास में जीत

आर्मी में अधिकारी बनने की राह आसान नहीं थी।

आभाष को लगातार छह बार असफलता मिली, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। सातवें प्रयास में आखिरकार उनका चयन हुआ और उन्होंने यह साबित कर दिया कि सच्चा जुनून और दृढ़ निश्चय किसी भी बाधा को पार कर सकता है।

शिक्षक माता-पिता से मिले संस्कार

आभाष के पिता श्री दिकपाल सिंह रहांगडाले और माता श्रीमती रेवंता रहांगडाले, दोनों ही शिक्षक हैं। घर में मिले संस्कारों ने ही उन्हें सिखाया कि सफलता का मापदंड पैसे या पद नहीं, बल्कि समाज और देश के लिए किया गया योगदान है। इन्हीं मूल्यों ने आभाष को असली योद्धा बनाया।

कलेक्टर सुश्री जैन से आत्मीय भेंट

भारतीय सेना में अधिकारी बनने के बाद बुधवार 10 सितम्बर को आभाष ने कलेक्टर सुश्री संस्कृति जैन से आत्मीय भेंट की।कलेक्टर सुश्री ने उन्हें सफलता की हार्दिक बधाई देते हुए कहा कि उनकी यह उपलब्धि पूरे जिले के लिए गर्व का विषय है। उनका संघर्ष और लगन युवाओं को प्रेरित करने वाला है।भेंट के दौरान कलेक्टर सुश्री जैन ने उन्हें जिले की शासकीय प्राथमिक शालाओं में जनसहयोग से डेस्क उपलब्ध कराने हेतु चलाई जा रही ÷गिफ्ट अ डेस्क÷ मुहिम की जानकारी दी।

इस पर आभाष ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा–यह केवल एक डेस्क दान करने का कार्य नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को मजबूत करने का प्रयास है। शिक्षा की नींव तभी मजबूत होगी जब बच्चों को बुनियादी सुविधाएँ मिलें। उन्होंने जिले के सभी नागरिकों से आग्रह किया कि इस मुहिम में सक्रिय भागीदारी करें और विद्यालयों की सुविधाओं को बेहतर बनाने में योगदान दें। जब समाज मिलकर शिक्षा में निवेश करता है, तभी सच्चा विकास संभव होता है।

युवाओं के लिए संदेश

लेफ्टिनेंट आभाष रहांगडाले ने युवाओं से कहा– ÷मैंने द्धद्धञ्ज, हृद्धञ्ज और कॉर्पोरेट करियर को नज़दीक से देखा है, लेकिन आत्मा की तृप्ति सिर्फ वर्दी पहनकर देश की सेवा करने में है। असफलताएँ मुझे बार-बार गिराने आई, लेकिन मेरा जुनून हर बार मुझे खड़ा करता गया। अगर आपके सपनों में देश है, तो हार का डर मन से निकाल दो। सफलता देर से मिलेगी, लेकिन जब मिलेगी तो वह पूरे समाज की होगी।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव टॉपर 7832 विद्यार्थियों को देंगे स्कूटी का उपहार

बालिकाओं को सेनिटेशन हाईजीन एवं वृतिका की राशि का भी सिंगल क्लिक से करेंगे अंतरण

कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में होगा आयोजन

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव शासकीय हायर सेकेन्डरी स्कूलों की 12वीं कक्षा में प्रथम स्थान अर्जित करने वाले 7832 विद्यार्थियों को निःशुल्क स्कूटी प्रदाय योजना के तहत राशि प्रदान करेंगे। कार्यक्रम का आयोजन 11 सितम्बर गुरूवार को भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में प्रातः 11 बजे से होगा। कार्यक्रम में स्कूल शिक्षा मंत्री श्री उदय प्रताप सिंह, जनजातीय कार्य मंत्री डॉ. कुंवर विजय शाह, खेल एवं युवा कल्याण, सहकारिता मंत्री श्री विश्वास सारंग, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री श्री चैतन्य कुमार काश्यप और पिछड़ा वर्ग एंव अल्पसंख्यक कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्रीमती कृष्णा गौर भी उपस्थित रहेंगी।

टॉपर्स विद्यार्थी को मिलेंगी स्कूटी की राशि

प्रदेश मे निःशुल्क ई-स्कूटी/आईसीईएस योजना शैक्षणिक सत्र 2022-23 से संचालित की जा रही हैं। इस योजना के अंतर्गत ऐसे छात्र-छात्राऐं पात्र होते हैं जिन्होंने प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग एवं जनजातीय कार्य विभाग अन्तर्गत संचालित शासकीय हायर सेकेण्डरी शाला में नियमित विद्यार्थी के रूप में अध्ययन कर माध्यमिक शिक्षा मण्डल की हायर सेकेण्ड्री कक्षा 12वीं में समस्त संकाय को शामिल कर अपनी शाला में नियमित परीक्षार्थी के रूप में टॉप किया हो। बालिका विद्यालय की दशा में स्कूल की टॉपर एक बालिका को, बालक विद्यालय होने की दशा में एक टॉपर बालक को एवं को-एड स्कूल जिसमें बालक बालिकाएं दोनों अध्ययनरत हों की दशा में स्कूल की एक टॉपर बालिका एवं एक टॉपर बालक अर्थात एक स्कूल से दो विद्यार्थियों को स्कूटी प्रदान किए जाने का प्रावधान है। वर्ष 2024-25 के लिए 12वीं की परीक्षा में 7,832 स्कूल टॉपर्स विद्यार्थियों को स्कूटी राशि प्रदान की जायेगी।

बालिकाओं को मिलेगी व्यक्तिगत स्वास्थ्य स्वच्छता की वृतिका राशि

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव समग्र शिक्षा की सेनिटेशन एवं हाईजीन योजना अंतर्गत वर्ष 2025 में कक्षा 7वीं से 12वीं की 20 लाख 37 हजार 439 बालिकाओं को लगभग 61 करोड़ रूपये डीबीटी द्वारा बालिकाओं के बैंक खाते में अंतरित करेंगे। इस योजना के तहत शासकीय विद्यालयों की कक्षा सातवीं से 12वीं तक अध्ययनरत बालिकाओं को स्वास्थ्य स्वच्छता के लिये300 रूपये की राशि प्रतिवर्ष प्रदान की जाती है।

20 हजार से अधिक बालिकाओं के बैंक खातों में 7 करोड का स्टायपंड

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव कार्यक्रम में 20 हजार 100 बालिकाओं के बैंक खातों में 7 करोड रूपयों की स्टायपंड राशि भी अंतरित करेंगे। उल्लेखनीय है कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय टाईप (द्धङ्क) योजना अंतर्गत छात्रावासों में निवासरत बालिकाओं को टी.एल.एम एवं स्टायपंड के लिए प्रति बालिका 3400 रूपये प्रति वर्ष प्रदान की जाती है।

कार्यक्रम का सजीव प्रसारण भी होगा

स्कूल शिक्षा विभाग और जनसंपर्क विभाग के द्वारा उक्त कार्यक्रम का सजीव प्रसारण विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्म्स पर किया जायेगा। एनआईसी वेबकास्ट के साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफार्मस् पर उक्त कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया जायेगा।

अखबार में प्रकाशन हेतु सूचना

प्रकाशन हेतु सूचना

यह सूचित किया जाता है कि स्व. दल सिंगार, निवासी मकान संख्या-136, जंगल बेनी माधव नं. 2, मोहरीपुर, तहसील सदर, जिला गोरखपुर, उत्तर प्रदेश (पिन कोड-273007) का दिनांक 06 मई 1997 को प्राकृतिक कारणों से निधन हो गया था।

उनकी पत्नी स्व. श्यामा देवी तथा माता-पिता स्व. रघुनंदन एवं स्व. जगदेई देवी का पूर्व में ही निधन हो चुका है। मृतक का धर्म हिंदू था और वे मजदूरी का कार्य करते थे।

श्री मुन्नीलाल चौहान (पुत्र) नगर निगम गोरखपुर से अपने पिता स्व. दल सिंगार का मृत्यु प्रमाण पत्र (Death Certificate) बनवाने हेतु आवेदन कर रहे हैं।

यदि किसी भी व्यक्ति को इस संबंध में कोई आपत्ति हो, तो वह इस सूचना के प्रकाशन के 7 कार्यदिवस के भीतर नगर निगम गोरखपुर को सूचित कर सकता है। यह सूचना विधिवत अभिलेख हेतु प्रकाशित की जा रही है।

मृतक का नामः स्व. दल सिंगार

पुत्र का नाम (आवेदक): श्री मुन्नीलाल चौहान

पताः मकान संख्या-136, जंगल बेनी माधव नं. 2, मोहरीपुर, तहसील सदर, जिला गोरखपुर, उत्तर प्रदेश - 273007

मृत्यु की तिथिः 06.05.1997

मृत्यु का कारणः प्राकृतिक

धर्मः हिंदू

व्यवसायः मजदूरी

उपयोगः

इस नोटिस को स्थानीय अखबार में ÷सूचना/मृत्यु सूचना÷ कॉलम में प्रकाशित कराएँ।

प्रकाशित अखबार की कटिंग नगर निगम में जमा कर दें।

इसके आधार पर मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।

सदर में कार में मिली सैन्य अधिकारी की लाश, जांच में जुटी पुलिस

जबलपुर/ प्रतिनिधि। सदर इंडियन कॉफ़ी हाउस के सामने पार्किंग में खड़ी कार में एक व्यक्ति का शव मिलने से हड़कंप मच गया। कार में शव होने की सूचना मिलते ही कैंट थाना का पुलिस बल मौके पर पहुंच गया।

कैंट थाना प्रभारी ने बताया कि सुबह 11।30 सूचना मिली थी सदर मेन रोड में खड़ी एक कार में कोई व्यक्ति अचेत अवस्था में ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ है। जिसके बाद पुलिस बल मौके पर पहुंचा। इसी दौरान आर्मी हास्पिटल का स्टाफ एंबुलेंस के साथ मौके पर पहुंच गया था। मिलिट्री हास्पिटल के स्टाफ ने बताया कि कार में मौजूद व्यक्ति मेजर वी विजय कुमार हैए जो कि मिलिट्री हास्पिटल जबलपुर में पदस्थ हैं।

इस दौरान आर्मी खुफिया विभाग के अधिकारियों को भी मौके पर पहुंच गए थे। एमएच के स्टाफ ने तत्काल कार में मौजूद सैन्य अधिकारी को हास्पिटल ले गए। जहां

चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।हालांकि प्रारंभिक तौर पर यह कहा जा रहा है कार सवार हैं सैन्य अधिकारी को हार्ट अटैक आया था, जिसके चलते उसकी कार की ड्राइविंग सीट पर ही मौत हो गई।

शादी का झांसा देकर वनकर्मी से रेप, कहा परिवार सहित आया था, सगाई से मुकर गया

जबलपुर/ प्रतिनिधि।वन विभाग मे पदस्थ एक महिला कर्मचारी ने पुलिस से मदद मांगी है। महिला का कहना है कि एक युवक ने परिवार के साथ घर आकर पहले सगाई की, इसके बाद मेलजोल बढ़ाया। अब शादी करने से मना कर रहा है।

32 वर्षीय महिला ने पुलिस अधिकारी को बताया कि शादी का झांसा देकर उसने ना सिर्फ दुष्कर्म किया। बल्कि जरूरत बता कर लाखों रुपए भी ले लिए। 5 साल तक शादी की बात करने वाला आरोपी युवक अब शादी करने से मना करते हुए धमकी दे रहा है कि अगर पुलिस तक पहुंची तो ठीक नहीं होगा। महिला की शिकायत सुनने के बाद सीएसपी ने ग्वारीघाट थाना प्रभारी को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

सगाई के बाद शादी से कर दिया मना-

महिला ने सीएसपी को बताया कि राजा गौंड नाम के व्यक्ति से उसकी पहचान हुई थी। परिवार के कुछ सदस्यों के साथ घर आकर शादी की

बात की। फिर सगाई हुई। लेकिन वह अब शादी से मना कर रहा है। वह युवती के मोबाइल में और घर पर रखी सगाई की फोटो भी ले गया।

अभी तक 5 लाख रुपए ले चुका-

पीड़िता का कहना है कि उसने सरकारी नौकरी देखकर उसके सामने शादी का प्रस्ताव रखा थाए इसके बाद वह कोई ना कोई जरूरत बताकर कभी 20 हजार तो कभी 34 हजार रुपए मांगे। अब तक वह 5 लाख रुपए ले चुका है।

पांच साल से संपर्क में है-

पीड़िता ने बताया कि 2020 में सगाई होने के बाद परिवार में कुछ ऐसी स्थिति आ गई थी कि शादी नहीं हो पाई। इसके बाद भी रमेश गौंड लगातार संपर्क में था, और यह कहता रहा कि जल्द ही शादी कर लेंगे पर नहीं किया। बीच में दोनों की बात बंद हो गई।

20 मई को शादी कर चुका है आरोपी-

2025 जनवरी में राजा एक बार फिर संपर्क में आया। दोनों का बात होना शुरू हो गई। पीड़िता ने बताया कि बिना किसी से कुछ कहे रमेश ने 20 मई को किसी और लड़की से शादी कर लिया। युवती ने जब रमेश से पूछा कि तुमने धोखा क्यों दिया। इस पर चुप रहने की धमकी देते हुए कहा कि दोबारा कभी मुझसे बात करनी कोशिश मत करना। शहर के गौरीघाट क्षेत्र में रहने वाली युवती की शिकायत को सीएसपी भगत सिंह गठोरिया ने गंभीरता से सुनने के बाद थाना प्रभारी ग्वारीघाट को निर्देश दिए है कि महिला कि शिकायत पर रमेश के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए।

सीएसपी ने बताया कि रमेश गौंड नाम का व्यक्ति जो कि मेडिकल कॉलेज में काम करता है। उसकी तलाश की जा रही है। जल्द ही वह पुलिस गिरफ्त में होगा। आरोपी ने ना सिर्फ महिला के साथ रेप किया है, बल्कि उससे लाखों रुपए भी ऐंठे हैं। दया। उन्होंने बताया कि इस सम्मान समारोह में स्वच्छ वायु परियोजना के नोडल अधिकारी संभव अयाची और उनकी टीम भी मौजूद थी, जिनकी लगन से यह संभव हो पाया है

नेशनल लोक अदालत में बिजली चोरी एवं अनियमितताओं के प्रकरणों में होंगे समझौते

लोक अदालत 13 सितंबर को

जबलपुर/ प्रतिनिधि। ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा है कि 13 सितंबर 2025 (शनिवार) को नेशनल लोक अदालत में बिजली चोरी एवं अन्य अनियमितताओं के प्रकरणों को समझौते के माध्यम से निराकृत किया जाएगा। उन्होंने विद्युत अधिनियम 2003 धारा 135 के अंतर्गत विद्युत चोरी के लंबित प्रकरणों एवं विशेष न्यायालयों में विचाराधीन प्रकरणों के निराकरण के लिए विद्युत उपभोक्ताओं एवं उपयोगकर्ताओं से अपील की है कि वे अप्रिय कानूनी कार्यवाही से बचने के लिए लोक अदालत में समझौता करने के लिए संबंधित बिजली कार्यालय से संपर्क करें।

धारा 135 के अंतर्गत विद्युत चोरी के बनाए गए लंबित प्रकरण एवं अदालत में लंबित प्रकरणों में निराकरण के लिये निम्नदाब श्रेणी के समस्त घरेलू, समस्त कृषि, 5 किलोवॉट तक के गैर घरेलू एवं 10 अश्व शक्ति भार तक के औद्योगिक उपभोक्ताओं में प्रकरणों में ही छूट दी जाएगी।

प्रि-लिटिगेशन स्तर पर - कंपनी द्वारा आकलित सिविल दायित्व की राशि पर 30 प्रतिशत एवं आकलित राशि के भुगतान में चूक किये जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात् प्रत्येक छः माही चक्रवृद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।

लिटिगेशन स्तर पर – कंपनी द्वारा आकलित सिविल दायित्व की राशि पर 20 प्रतिशत एवं आकलित राशि के भुगतान में चूक किये जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात् प्रत्येक छःमाही चक्रवृद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत छूट दी जाएगी।

कंपनी ने कहा है कि नेशनल लोक अदालत में छूट कुछ नियम एवं शर्तो के तहत दी जाएगी जो आकलित सिविल दायित्व राशि रू. 10,00,000 (दस लाख) तक के प्रकरणों के लिए सीमित रहेगी। यह छूट मात्र नेशनल ''लोक अदालत'' 13 सितंबर 2025 को समझौते करने के लिये ही लागू रहेगी।

विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126 के लंबित प्रकरणों में भी लोक अदालत की तर्ज पर छूट प्रदान कर प्रकरणों का निराकरण भी लोक अदालत के माह के दौरान किया जाएगा। लोक अदालत की प्रक्रिया के अनुरूप निर्धारित मापदंडों के अधीन 10 लाख रूपए तक की सिविल दायित्व की राशि के समस्त घरेलू, समस्त कृषि, 5 किलोवाट तक गैर घरेलू व 10 अश्वशक्ति के औद्योगिक श्रेणी के लंबित प्रकरणों का आवेदन संबंधित उप महा प्रबंधक को देना होगा, आकलित राशि पर 20 प्रतिशत एवं अधिशासित ब्याज राशि के भुगतान में चूक किए जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने पर, इसके पश्चात प्रत्येक 6 माही चक्रवर्ती ब्याज अनुरूप 16 प्रतिशत की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर, 100 फीसदी की छूट दी जाएगी। बशर्ते किसी प्रकरण में धारा 127 के अंतर्गत गठित अपील प्राधिकरण के समक्ष अथवा उच्च न्यायालय में कोई अपील लंबित न हो।

पीएम-जनमन कार्यक्रम : आंगनवाड़ी भवनों के निर्माण में म.प्र. देश में अव्वल

विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा, भारिया और सहरिया समुदाय को मिलेगा लाभ

जबलपुर/ प्रतिनिधि। प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय अभियान के अंतर्गत मध्यप्रदेश ने एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। प्रदेश में निवासरत विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा, भारिया और सहरिया समुदाय के लिये स्वीकृत 217 आंगनवाड़ी भवनों में से 100 भवनों का तय समय-सीमा से पहले निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। इस उपलब्धि के साथ मध्यप्रदेश योजना के क्रियान्वयन में देश का अग्रणी राज्य बन गया है। निर्धारित लक्ष्य की दिशा में ठोस कदम उठाते हुए प्रथम चरण में बड़ी प्रगति दर्ज करते हुए शेष 117 आंगनवाड़ी भवनों का निर्माण 31 मार्च 2026 तक पूरा कर लिया जाएगा। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2024 से 2026 के बीच संचालित बहुउद्देशीय पीएम-जनमन अभियान का मुख्य उद्देश्य विशेष पिछड़ी जनजातीय समूहों बैगा, भारिया और सहरिया समुदायों को शिक्षा, पोषण, स्वास्थ्य और आधारभूत सुविधाओं से जोड़ना है। इस अभियान में नये आंगनवाड़ी केंद्रों का निर्माण, पक्के भवनों की व्यवस्था और पूरक पोषण आहार का नियमित प्रदाय सुनिश्चित किया जा रहा है। इन आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होगा, बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा एवं पोषण मिलेगा, साथ ही जनजातीय समुदायों के समग्र विकास को प्रोत्साहन मिलेगा। शिवपुरी जिले में 39, श्योपुर में 37, शहडोल में 29, उमरिया में 23, गुना में 14, डिंडौरी में 12, अशोकनगर में 11, अनूपपुर में 7, मंडला एवं दतिया में 6-6, विदिशा, बालाघाट, ग्वालियर एवं सीधी में 5-5, जबलपुर एवं छिंदवाड़ा में 4-4, मुरैना में 2 तथा कटनी, भिंड और रायसेन में 1-1 आंगनवाड़ी भवन स्वीकृत किए गए हैं। प्रत्येक भवन पर लगभग 12 लाख रुपये का व्यय किया जा रहा है। यह पहल जनजातीय बहुल इलाकों में नई उम्मीद और बदलाव की शुरुआत है। आंगनवाड़ी भवनों का निर्माण केवल भौतिक संरचना नहीं बल्कि सामाजिक-आर्थिक विकास का मजबूत आधार भी है। इनके माध्यम से जहां बच्चों को बेहतर पोषण और शिक्षा उपलब्ध होगी, वहीं महिलाओं के स्वास्थ्य एवं सशक्तिकरण में भी उल्लेखनीय सुधार आएगा। प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय अभियान का यह चरण देश में जनजातीय कल्याण के लिए एक आदर्श मॉडल के रूप में देखा जा रहा है और मध्यप्रदेश ने इसे लागू करने में अग्रणी भूमिका निभाई है।

प्रदेश के 9300 हाई एवं हायर सेकण्डरी स्कूलों में 12 सितंबर को उमंग दिवस

बच्चों को जीवन कौशल शिक्षा देने के लिये चलाया जा रहा है कार्यक्रम

उमंग है तो जिंदगी में रंग है÷ इस थीम पर आधारित उमंग दिवस का आयोजन 12 सितम्बर को प्रदेश के 9 हजार 300 हाई एवं हायर सेकेंडरी स्कूलों में किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का लाभ 20 लाख से अधिक बच्चों को मिलेगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों को विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) द्वारा निर्धारित 10 जीवन कौशलों से परिचित करवाना है। कार्यक्रम की मदद से बच्चे जीवन में आने वाले चुनौतियों का सामना मजबूती से कर सकेंगे। कार्यक्रम का एक और उद्देश्य है कि बच्चों को जीवन में आगे बढ़ने के लिए तैयार किया जाये।

यह कार्यक्रम स्कूल शिक्षा विभाग एवं संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (यूएनएफपीए) के सहयोग से तैयार किया गया है। जीवन कौशल शिक्षा आधारित करिकुलम और उसके संचालन में की गई पिछले 7 वर्षों की कड़ी मेहनत से बच्चों के जीवन में आए सकारात्मक बदलाव को उत्साह के रूप में मनाना है। कार्यक्रम में बच्चे एक-दूसरे के अनुभवों को साझा करते हैं और अन्य विद्यार्थियों को प्रोत्साहित एवं मार्गदर्शित करते है। उमंग स्कूल हेल्थ एवं वेलनेस कार्यक्रम एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है जिसमें गतिविधि आधारित कक्षावार जीवन कौशल शिक्षा के मॉड्यूल हैं जिसे शिक्षा विभाग, स्वास्थ विभाग एवं यूनाईटेड नेशन्स पॉप्युलेशन फंड (यूएनएफपीए) की बराबर भागीदारी से मिलकर चलाया जा रहा है। प्रदेश की सभी शासकीय हाई एवं हॉयर सेकेंडरी स्कूलों में प्रत्येक मंगलवार को एक सत्र लिया जाता है। प्रत्येक शाला से 2 शिक्षकों को (एक पुरुष एवं एक महिला) हेल्थ एवं वेलनेस एंबेसेडर के रूप में प्रशिक्षित किया गया है। राज्य में अब तक लगभग 19 हजार शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। यह प्रशिक्षित शिक्षक हेल्थ एंड वैलनेस एम्बेसडर कक्षाओं में जीवन कौशल गतिविधियों का संचालन करते हैं। उमंग दिवस के कार्यक्रम में विभिन्न विभाग के अधिकारी एवं मोटिवेशनल वक्ताओं को भी शिक्षण संस्था में आमंत्रित किया जाएगा, जिससे विद्यार्थी आगे बढ़ाने के लिए और उत्साह पूर्वक कदम बढ़ाने के लिए प्रेरित हो सकें। इस कार्यक्रम में न केवल विद्यार्थियों को बल्कि शाला में उपस्थित प्रत्येक शिक्षक को भी इस विषय से अवगत होने का मौका मिलेगा।

स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में जबलपुर को देश में दूसरा स्थान मिलने पर महापौर और निगमायुक्त के नगर आगमन पर भव्य स्वागत

स्वच्छता में देश में पॉचवॉ स्थान, 7 स्टार रैंकिंग, गार्बेज फ्री सिटी, वॉटर प्लस सिटी का दर्जा प्राप्त होने के साथ-साथ देश का पहला नगर निगम जहॉ सफाई संरक्षकों की सुरक्षा मानकों पर देश में अव्वल स्थान बनाया है जबलपुर

जबलपुर/ प्रतिनिधि। देश की राजधानी दिल्ली में आयोजित स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में नगर निगम जबलपुर को एक बड़ी और ऐतिहासिक सफलता मिली, जिसके कारण देश के मानचित्र पर जबलपुर का नाम गौरवांवित हो रहा है तथा देश के बेहतरीन शहरों में शामिल हुआ है. इस संबंध में महापौर जगत बहादुर सिंह ''अन्नू'', निगमायुक्त श्रीमती प्रीति यादव एवं स्वच्छता सेल के संभव अयाची ने जानकारी देते हुए बताया कि स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 के प्रतियोगिता में भारत सरकार द्वारा दिल्ली में आयोजित सम्मान समारोह में नगर निगम जबलपुर को बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है. इस उपलब्धि से उत्साहित होकर आज महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू के नगर आगमन पर डुमना एयरपोर्ट पहुंचकर शहर के गणमान्य जनों, जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, कर्मचारियों एवं स्नेहीजनों ने भव्य स्वागत किया.

इस अवसर पर महापौर ने स्वागत और सम्मान पाकर अभिभूत हुए और संस्कारधानी के देवतुल्य नागरिकों, जनप्रतिनिधियों, कर्मचारी संघों, अधिकारियों कर्मचारियों और स्नेहीजनों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि विगत 3 महीनों में नगर निगम जबलपुर को स्वच्छता में देश में पॉचवॉ स्थान मिलने के बाद अब स्वच्छ वायु सर्वेक्षण प्रतियोगिता में भी देश में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है, जो एक गौरव की बात है.

उन्होंने कहा कि देवतुल्य नागरिकों के संकल्प, जागरूकता, जनभागीदारी एवं अपने शहर के प्रति प्रेम ने यह उपलब्धि दिलाई है. महापौर ने बताया कि उनके कार्यकाल का यह वर्ष स्वर्णिम कार्यकाल माना जायेगा, क्योंकि स्वच्छता, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण के अलावा राष्ट्रीय शहर आजीविका मिशन एवं अन्य कार्यो के लिए भी राष्ट्रीय स्तर पर नगर निगम जबलपुर को सम्मानित किया जा चुका है. उन्होंने बताया कि स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में देश में दूसरा स्थान प्राप्त करने के पूर्व स्वच्छता में देश में पॉचवॉ स्थान, 7 स्टार रैंकिंग, गार्बेज फ्री सिटी, वॉटर प्लस सिटी, का दर्जा प्राप्त कर सफाई संरक्षकों की सुरक्षा मानकों पर भी देश में अव्वल स्थान बनाया है. उन्होंने कहा कि निगम अधिकारियों कर्मचारियों की कड़ी मेहनत रंग लाई है.

महापौर ने उपलब्धियों की जानकारी देते हुए बहुत ही गर्व के साथ जानकारी दी कि देश की इकलौती नगरीय निकाय जबलपुर क्षेत्र है, जहॉ मॉ नर्मदा में गंदे नाले का पानी नहीं मिलता है. महापौर ने उपस्थित सभी जनों के सामने यह संकल्प दोहराया कि आगे स्वच्छता एवं स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में जबलपुर को पहला स्थान दिलाने सामूहिक रूप से सार्थक प्रयास किया जायेगा. नगर निगम जबलपुर को मिली बड़ी उपलब्धियों के लिए उन्होंने विशेषकर संस्कारधानी के देवतुल्य नागरिकों के प्रति आभार व्यक्त किया है.

आज भव्य स्वागत सम्मान के दौरान नगर निगम के अध्यक्ष रिकुंज विज, एम.आई.सी. सदस्य एवं स्वास्थ्य प्रभारी श्रीमती रजनी कैलाष साहू, एम.आई.सी. सदस्य डॉ. सुभाष तिवारी, दामोदर सोनी, विवेकराम सोनकर, श्रीमती अंषुल राघवेन्द्र यादव, पार्षद गण - श्रीमती माधुरी सोनकर, अतुल जैन, श्रीमती प्रतिभा भापकर, मधुबाला राजपूत, अनुराग साहू (राहुल), सुनील पुरी गोस्वामी, श्रीमती पूजा श्रीराम पटैल, श्रीमती निशा संजय राठौर, श्रीमती लवलीन आनंद, श्रीमती रेणु राकेश कोरी, श्रीमती लक्ष्मी जय चक्रवर्ती, जितेन्द्र कटारे (जीतू), श्रीमती सोनिया रंजीत सिंह, श्रीमती कविता रैकवार, श्रीमती मोनिका सिंह क्षत्रि, श्रीमती अविनाश चमकेल, श्रीमती वर्षा मुकेश बिरहा, श्रीमती अंजू अनीता जाट (गोलू), श्रीमती रंजना रंजू ठाकुर, जितेन्द्र कश्यप गोवर्धन, विमल राय, श्रीमती अंजना अग्रहरि, शरद श्रीवास्तव, अनुराग दाहिया, निशांत झारिया, श्रीमती संतोषी ठाकुर, श्याम कुमार कनौजिया, कृष्णा दास चौधरी, श्रीमती सावित्री शाह गोड, श्रीमती अर्चना सिसौदिया, योगेन्द्र उइके, श्रीमती रजनी सुरेन्द्र साहू, अपर आयुक्त व्ही.एन. बाजपेयी, प्रशांत गोटिया, मनोज श्रीवास्तव, श्रीमती अंजू सिंह ठाकुर, पूर्व अपर आयुक्त राकेश अयाची, अधीक्षण यंत्री कमलेश श्रीवास्तव, कार्यपालन यंत्री शैलेन्द्र मिश्रा, नवीन लोनारे, जी.एस. मरावी, पूर्व कार्य पालन यंत्री अजय शर्मा, कार्यपालन यंत्री शैलेन्द्र कौरव, जागेन्द्र सिंह, उद्यान अधिकारी आलोक शुक्ला, फायर अधीक्षक कुसाग्र ठाकुर, सहायक अधीक्षक राजेन्द्र पटैल, कार्यालय अधीक्षक दिलीप दुबे, कॉलोनी सेल प्रभारी सुनील दुबे, सहायक यंत्री अभिनव मिश्रा, राजस्व अधीक्षक इन्द्र कुमार वर्मा, सहायक स्वास्थ्य अधिकारी अनिल बारी, धमेन्द्र राज, अर्जुन यादव, पोलाराव, सभी संभागीय अधिकारी, समस्त मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक, स्वास्थ्य निरीक्षक, वार्ड सुपरवाईजर के साथ कर्मचारी संघों के पदाधिकारी राजेन्द्र पटैल, कपिल दुबे, अमित मेहरा, राकेश समुद्रे, आदि ने भी उपस्थित होकर स्वागत एवं सम्मान किया.

मैहर में सड़क पर बनी सड़क, ऊंचाई हो गई 1 फीट, घरों में पानी भरा, जबलपुर हाईकोर्ट पहुंचा रहवासी, बेंच ने पूछा, कौन करता है अप्रूव

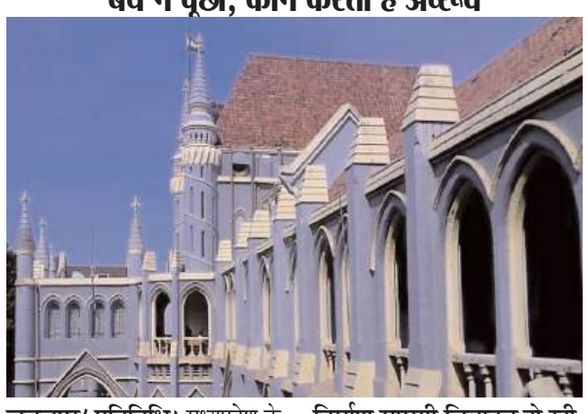

जबलपुर/ प्रतिनिधि। मध्यप्रदेश के मैहर में लोक निर्माण विभाग की कार्यशैली से लोग परेशान हैं। पीडब्ल्यू ने शहर के बीचो-बीच 4 किमी की सड़क को एक फीट तक ऊंचा कर दिया है। इससे बारिश का पानी मकान और दुकानों में भरा रहा है। इतना ही नहीं रोड अधिक ऊंचाई पर होने से लोगों को आने-जाने में भी परेशानी हो रही है।

मामले को लेकर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई। जिस पर चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने सुनवाई की। बेंच ने कहा कि बड़ी ही अचरज की बात है। ऐसे कार्यों को आखिर कौन अप्रूव कौन कर रहा है। हाईकोर्ट ने मैहर नगर पालिका और ठेकेदारों सहित अन्य से जवाब तलब किया है। अगली सुनवाई 24 सितंबर को होगी। मैहर बस स्टैंड हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में रहने वाले मनीष पटेल की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। अधिवक्ता जयंत कुमार पटेल ने उनका पक्ष रखा। उन्होंने कोर्ट को बताया कि मां शारदा मंदिर के रोप-वे के पास घंटाघर तक करीब 4 किलोमीटर की सड़क का निर्माण किया जा रहा है। यह सड़क अलाउद्दीन चौराहे व कलेक्ट्रेट होते हुए गुजरेगी। मैहर शहर के बीचों-बीच की सड़क एक फीट तक ऊंची हो गई है। जिससे रहवासी परेशान हैं। याचिकाकर्ता ने बताया कि सड़क निर्माण में भारी अनियमितताएं हो रही है। सड़क पहले ही 2 बार बन चुकी है। फिर भी बारिश के समय हालात और भी खराब हो जाते हैं। ऊंचाई अधिक होने से दुर्घटनाओं का अंदेशा भी बना रहता है।

निर्माण सामग्री बिछाकर हो रही खानापूर्ति-

याचिका में यह भी आरोप लगाया है कि लोक निर्माण विभाग और स्थानीय ठेकेदार बिना आधार के कार्य कर रहे हैं। जिससे सड़क पर सिर्फ निर्माण सामग्री बिछाकर खानापूर्ति की जा रही है। हाईकोर्ट को बताया गया कि पुरानी सड़क को तोडऩे की बजाय उस पर ही नया निर्माण किया जा रहा है। तीसरी बार ऐसा हुआ है। हाईकोर्ट ने लोक निर्माण विभाग के वकील से पूछा है कि आखिर ऐसी क्या आवश्यकता आ गई कि तीन बार एक ही सड़क पर निर्माण करवाया जा रहा है। क्या इस सड़क पर भारी वाहनों का आवागमन होता है।

बेंच ने कहा,तर्क सही, हर जगह यही कर रहे हैं

मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा और न्यायमूर्ति विनय सराफ की पीठ ने मौखिक रूप से कहा कि देखिए उठाया गया तर्क सही है। ऊंचाई देखिए, आप सड़क की ऊंचाई एक फीट बढ़ा रहे हैं। इसकी क्या जरूरत है, हर जगह आप यही कर रहे हैं। अब घर पानी में डूब जाएंगे। इस एक फीट ऊंची सड़क को बनाने का क्या कारण है। जबलपुर में भी हम हवाईअड्डे से यहां तक देख रहे हैं। ऊंचाई बढ़ गई है। घर पानी में डूब रहे हैं तो सड़क के इस डिजाइन को किसने मंजूरी दी कि यह मौजूदा सड़क से एक फीट ऊंची होनी चाहिए। याचिका में प्रमुख सचिव निर्माण भवन, प्रमुख सचिव नगरीय प्रशासन विभाग, इंजीनियर इन चीफ, ईई पीडब्ल्यूडी संभाग सतना, एसडीओ पीडब्ल्यूडी मैहर, कलेक्टर मैहर, नगर पालिका मैहर व ठेकेदार संजय सिंह को पक्षकार बनाया है।

जबलपुर में देश का पहला हिंदी चिकित्सा कॉलेज शुरू होने की तैयारी

जबलपुर/ प्रतिनिधि। मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय जल्द ही जबलपुर में देश का पहला हिंदी माध्यम चिकित्सा कॉलेज शुरू करने की तैयारी कर रहा है। सूत्रों के अनुसार, यह कॉलेज एमबीबीएस की 50 सीटों के साथ शैक्षणिक सत्र 2027-28 से आरम्भ किया जाएगा। इस परियोजना के लिए प्रारंभिक बजट लगभग एक करोड़ रुपये रखा गया है। मध्यप्रदेश की शिक्षा व्यवस्था एक ऐतिहासिक कदम की ओर बढ़ रही है। विश्वविद्यालय की ओर से तैयार योजना के मुताबिक यह कॉलेज एमबीबीएस की 50 सीटों के साथ शैक्षणिक सत्र 2027-28 से प्रारंभ होगा। प्रारंभिक बजट एक करोड़ रुपये तय किया गया है। इस खबर ने प्रदेश के शिक्षा जगत और चिकित्सा क्षेत्र दोनों में उत्साह का वातावरण बना दिया है।

अब तक चिकित्सा शिक्षा का माध्यम केवल अंग्रेजी ही रहा है। देश में हर साल लाखों छात्र डॉक्टर बनने का सपना लेकर मेडिकल प्रवेश परीक्षाएँ देते हैं, लेकिन ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने वाले विद्यार्थियों के लिए भाषा हमेशा से बड़ी चुनौती रही है। मेडिकल की जटिल शब्दावली और अंग्रेजी पर निर्भरता के कारण अनेक प्रतिभाशाली विद्यार्थी आगे नहीं बढ़ पाते। हिंदी माध्यम कॉलेज की शुरुआत से यह बाधा काफी हद तक टूटेगी और उन छात्रों को अवसर मिलेगा, जिनकी मातृभाषा हिंदी है।

सूत्रों के अनुसार, विश्वविद्यालय प्रशासन ने इस परियोजना को गंभीरता से आगे बढ़ाने के लिए विशेषज्ञ समितियाँ गठित कर दी हैं। एमबीबीएस पाठ्यक्रम का हिंदी अनुवाद पहले से तैयार किया जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि अनुवाद केवल शब्दशः न होकर वैज्ञानिक दृष्टि से सटीक और सहज होगा ताकि छात्रों को विषय की गहराई समझने में कोई कठिनाई न हो। उदाहरण के लिए एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और बायोकैमिस्ट्री जैसे विषयों को हिंदी में सरल व्याख्या और स्थानीय शब्दावली के साथ पढ़ाया जाएगा।

पाठ्यक्रम की संरचना इस तरह बनाई जा रही है कि छात्रों को हिंदी में शिक्षा मिलते हुए भी अंग्रेजी की मूल शब्दावली से परिचित कराया जाए। इसका उद्देश्य यह है कि डॉक्टर बनने के बाद उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काम करने या शोध कार्यों से जुड़ने में कठिनाई न हो। चिकित्सा जगत का अधिकांश साहित्य अंग्रेजी में उपलब्ध है, इसलिए छात्रों को द्विभाषी

मॉडल के तहत प्रशिक्षित करने की योजना है।

जबलपुर को इस परियोजना के लिए चुना जाना भी संयोग नहीं है। यह शहर लंबे समय से शिक्षा और न्याय का केंद्र रहा है। यहाँ मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय का मुख्यालय भी है, जिससे कॉलेज की स्थापना के लिए आवश्यक शैक्षणिक संसाधन और प्रशासनिक सुविधाएँ पहले से मौजूद हैं। जबलपुर की पहचान सांस्कृतिक और बौद्धिक माहौल के लिए रही है और अब यह हिंदी चिकित्सा शिक्षा का पथप्रदर्शक बनने जा रहा है।

इस पहल पर छात्रों और अभिभावकों की प्रतिक्रियाएँ बेहद सकारात्मक हैं। सोशल मीडिया पर अनेक छात्रों ने लिखा कि हिंदी में मेडिकल शिक्षा शुरू होना उनके लिए सपनों को पंख देने जैसा है। खासकर वे छात्र जो अब तक अंग्रेजी की वजह से पीछे छूट रहे थे, वे इसे अपनी जिंदगी बदलने वाला मौका मान रहे हैं।

राज्य सरकार ने भी इस योजना को ऐतिहासिक बताया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने हाल ही में कहा था कि मातृभाषा में शिक्षा देना न केवल आत्मनिर्भरता की ओर कदम है, बल्कि इससे छात्रों का आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि भविष्य में इंजीनियरिंग और अन्य तकनीकी विषयों में भी हिंदी माध्यम को प्रोत्साहित किया जाएगा।

हालांकि, विशेषज्ञों की राय पूरी तरह एक जैसी नहीं है। कुछ चिकित्सा विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम ग्रामीण छात्रों के लिए वरदान साबित होगा और वे डॉक्टर बनने की दौड़ में बराबरी से भाग ले पाएंगे। उनका कहना है कि रोगियों से संवाद करने में भी यह प्रयोग कारगर साबित होगा, क्योंकि अधिकतर मरीज हिंदी भाषी होते हैं और डॉक्टर यदि उनकी भाषा में ही संवाद करेंगे तो उपचार अधिक प्रभावी होगा। दूसरी ओर कुछ विशेषज्ञों का मत है कि केवल हिंदी माध्यम पर आधारित शिक्षा से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करना कठिन हो सकता है। लेकिन विश्वविद्यालय ने स्पष्ट किया है कि द्विभाषी व्यवस्था के तहत छात्रों को अंग्रेजी की आवश्यक जानकारी भी दी जाएगी।

सामाजिक दृष्टि से यह पहल भाषा को सम्मान दिलाने वाली है। लंबे समय से यह बहस चल रही थी कि आखिर क्यों विज्ञान और चिकित्सा जैसे विषयों को केवल अंग्रेजी में पढ़ाया जाता है। हिंदी माध्यम चिकित्सा कॉलेज इस बहस का व्यावहारिक उत्तर बनेगा। यह दिखाएगा कि विज्ञान की गहराई मातृभाषा में भी उतनी ही प्रभावशाली तरीके से पढ़ाई जा सकती है। यह कॉलेज अवसर की समानता का प्रतीक भी बनेगा। अब वह वर्ग भी डॉक्टर बनने का सपना पूरा कर सकेगा जो अंग्रेजी के अभाव में पीछे रह जाता था। यह सीधे-सीधे सामाजिक न्याय का सवाल है और हिंदी माध्यम मेडिकल कॉलेज उसका समाधान प्रस्तुत करेगा। विशेषज्ञों का अनुमान है कि यदि यह प्रयोग सफल होता है तो आने वाले वर्षों में अन्य राज्यों में भी इसी तरह के कॉलेज खुलेंगे। उत्तरप्रदेश और कर्नाटक जैसे राज्यों ने भी मातृभाषा में मेडिकल शिक्षा की दिशा में प्रयास शुरू किए हैं, लेकिन जबलपुर इस क्षेत्र में अग्रणी साबित हो सकता है। इस कॉलेज की स्थापना केवल एक नई संस्था की शुरुआत नहीं होगी, बल्कि शिक्षा व्यवस्था में एक नए अध्याय का उदय होगा। यह संदेश जाएगा कि भाषा कभी भी ज्ञान की राह में बाधा नहीं बनती, बल्कि समझ और संवाद को और गहरा करती है। जबलपुर में प्रस्तावित हिंदी चिकित्सा कॉलेज का महत्व केवल प्रदेश तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह राष्ट्रीय स्तर पर भी चिकित्सा शिक्षा के लिए नए रास्ते खोलेगा। यह पहल साबित करेगी कि इच्छाशक्ति और दूर दृष्टि से बदलाव संभव है और मातृभाषा में शिक्षा देकर भी डॉक्टरों की नई पीढ़ी तैयार की जा सकती है।

आईटी पार्क में मिला 5 फीट लंबा कोबरा नाग सर्प विशेषज्ञ ने सुरक्षित किया रेस्क्यू

जबलपुर/ प्रतिनिधि। । शहर के आईटी पार्क परिसर में सोमवार देर रात एक पांच फीट लंबा कोबरा नाग निकलने से हड़कंप मच गया। वहां मौजूद कर्मचारियों और स्थानीय लोगों ने तत्काल इसकी सूचना वन विभाग और सर्प विशेषज्ञों को दी। सूचना मिलते ही सर्प विशेषज्ञ मौके पर पहुँचे और करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद कोबरा को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे लोग बड़ी संख्या में शेयर कर रहे हैं।

आईटी पार्क में मौजूद युवाओं ने नाग के रेंगते हुए बाहर निकलने का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया। देखते ही देखते यह वीडियो वायरल हो गया और सैकड़ों लोगों ने इसे शेयर कर दिया। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कोबरा फन फैलाए हुए है और सर्प विशेषज्ञ सावधानीपूर्वक उसे नियंत्रित कर रहे हैं। लोगों ने इस साहसिक कार्य की सराहना की और कहा कि सर्प विशेषज्ञों की वजह से एक बड़ी दुर्घटना टल गई।

आईटी पार्क में देर रात कई कर्मचारी काम कर रहे थे। अचानक नाग को देख कर्मचारियों में अफरा-तफरी मच गई। कुछ लोग भागकर इमारत के बाहर निकल आए, तो कुछ ने सुरक्षित दूरी बनाकर मोबाइल से घटना रिकॉर्ड की। स्थानीय लोगों का कहना है कि हाल के दिनों में बारिश और नमी बढ़ने से साँपों के शहर

के रिहायशी और व्यावसायिक इलाकों में घुसने की घटनाएँ बढ़ गई हैं। रेस्क्यू करने वाले सर्प विशेषज्ञ ने बताया कि यह एक वयस्क कोबरा था, जिसकी लंबाई लगभग पांच फीट रही। उन्होंने कहा कि कोबरा बेहद जहरीला होता है और जरा सी लापरवाही से जान पर बन सकती थी। उन्होंने लोगों से अपील की कि ऐसे हालात में खुद से साँप पकड़ने की कोशिश न करें और तुरंत विशेषज्ञों को बुलाएँ। रेस्क्यू के बाद नाग को सुरक्षित वन क्षेत्र में छोड़ा गया। वन विभाग अधिकारियों ने कहा कि बारिश के मौसम में सांप अपने बिलों से निकलकर सुरक्षित जगह तलाशते हैं और अक्सर रिहायशी इलाकों में आ जाते हैं। इस समय लोगों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। खासतौर पर झाड़ियों और नमी वाले इलाकों में अनावश्यक रूप से न घूमें और यदि कहीं साँप दिखे तो तुरंत वन विभाग की हेल्पलाइन पर जानकारी दें।

इस घटना के बाद आईटी पार्क के कर्मचारियों ने कहा कि परिसर में ऐसी घटनाएँ पहले भी हो चुकी हैं। उन्होंने प्रशासन से अपील की कि पार्क और आसपास के क्षेत्र में नियमित रूप से सफाई और झाड़ियों की कटाई कराई जाए। कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर टिप्पणी की कि रेस्क्यू टीम का काम काबिले तारीफ है और शहर में ऐसे प्रशिक्षित लोगों की संख्या और बढ़ाई जानी चाहिए। विशेषज्ञों का कहना है कि आम लोगों में अब भी सांपों को लेकर डर और अंधविश्वास बहुत है। जबकि सच यह है कि सांप पारिस्थितिकी तंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और उन्हें मारना उचित नहीं है। ऐसे मामलों में जागरूकता कार्यक्रम चलाने की आवश्यकता है, ताकि लोग न केवल खुद सुरक्षित रहें बल्कि वन्य जीवों की भी रक्षा हो सके। आईटी पार्क में कोबरा नाग मिलने की यह घटना भले ही कुछ देर की दहशत का कारण बनी, लेकिन सर्प विशेषज्ञों की तत्परता और साहसिक प्रयास ने स्थिति को संभाल लिया। यह घटना हमें यह भी याद दिलाती है कि शहरीकरण के बीच वन्य जीवों के लिए सुरक्षित आवास कम होते जा रहे हैं और वे इंसानी बस्तियों की ओर रुख करने लगे हैं। ऐसे में समाज और प्रशासन दोनों को मिलकर संतुलन बनाने की आवश्यकता है।

जनसुनवाई में प्राप्त हुए 10 प्रकरण

जबलपुर। निगमायुक्त श्रीमती प्रीति यादव के निर्देशानुसार सहायक आयुक्त वेदप्रकाश ने जनसुनवाई कक्ष में आज दिनांक 09 सितम्बर 2025 को प्रातः 11:00 बजे से 01:00 बजे तक नागरिकों की समस्याएँ सुनी। इस दौरान अतिक्रमण की 3, स्थापना शाख की 2, राजस्व विभाग की 1, सम्पदा शाखा की 1, भवन शाखा की 2, जल विभाग की 1, कुल 10 जनसमस्याएँ प्राप्त हुई, जिसका निराकरण सुनवाई के दौरान ही किया गया। सहायक आयुक्त वेदप्रकाश ने बताया कि सभी प्राप्त शिकायतें संबंधित अधिकारियों को जल्द से जल्द निराकरण हेतु प्रेषित की गयी हैं। उन्होंने बताया कि नगर निगम के संभाग क्रमांक 1 से 16 में भी जनसुनवाई का आयोजन किया गया तथा नागरिकों की समस्याएँ सुनी गई और उनका निराकरण भी कराया गया।

माँ नर्मदा की उद्गम स्थली में कपिलधारा पहुँच मार्ग का भूमिपूजन

गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होगा : लोक निर्माण मंत्री

जबलपुर/ प्रतिनिधि। । लोक निर्माण मंत्री श्री राकेश सिंह ने अमरकंटक में कपिलधारा पहुँच मार्ग का भूमिपूजन किया। माँ नर्मदा की उद्गम स्थली को नमन करते हुए उन्होंने कहा कि यह मार्ग केवल सड़क नहीं बल्कि श्रद्धा और आस्था को आधुनिकता से जोड़ने वाला पथ बनेगा।

कपिलधारा जलप्रपात, जिसे ऋषि कपिल की तपोभूमि माना जाता है, हर वर्ष लाखों श्रद्धालुओं और पर्यटकों को आकर्षित करता है। मंत्री श्री सिंह ने बताया कि पाँच किलोमीटर लंबे इस नए पहुँच मार्ग को ऐसा रूप दिया जाएगा, जिससे यह केवल सड़क न लगकर एक पर्यटन स्थल जैसा अनुभव प्रदान करेगा।इस दो लेन चौड़े मार्ग पर पैदल यात्रियों के लिए फुटपाथ, छायादार आश्रय स्थल, कम्पोस्ट शौचालय और सौर ऊर्जा से संचालित दीपक लगाए जाएँगे। मार्ग की बाउंड्री पर कपिल मुनि की तपस्या, राजा सगर के पुत्रों और माँ गंगा के अवतरण की गाथाएँ उकेरी जाएँगी। मंत्री श्री सिंह ने कहा कि यह मॉडल भीमबेटका और भोजपुर जैसे स्थलों पर भी लागू किया जाएगा।

समीक्षा बैठक में विभागीय निर्णय

लोक निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक में प्रदेश के मुख्य अभियंता उपस्थित रहे। बैठक में विभागीय प्रस्तुतियाँ दी गईं। मंत्री श्री सिंह ने गुणवत्ता पर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि किसी भी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि कुछ अधिकारियों ने औचक निरीक्षणों में सख्ती दिखाई है, वहीं कुछ ने बिल्कुल भी कार्रवाई नहीं की। यह रवैया अब स्वीकार्य नहीं होगा। उन्होंने घोषणा की कि अच्छा काम करने वालों को सम्मान और लापरवाही करने वालों को दंड मिलेगा।

लोक कल्याण सरोवर योजना पर जोर

बैठक में लोक कल्याण सरोवर योजना पर चर्चा हुई। मंत्री श्री सिंह ने निर्देश दिए कि प्रत्येक परिक्षेत्र में 10-10 सरोवरों का चयन कर मुख्य अभियंता स्वयं उनका भौतिक निरीक्षण करें। इन सरोवरों पर सूचना पट्टिकाएँ लगाई जाएँ और इन्हें स्थानीय समाज के लिए उपयोगी धरोहर बनाया जाए।

टेक्नोलॉजी आधारित नवाचार

मंत्री श्री सिंह ने बताया कि 18 से 20 सितम्बर तक प्रदेश की सभी सड़कों और पुलों का सर्वेक्षण रोड ट्रेकिंग एंड सर्वे मोबाइल ऐप से किया जाएगा। यह ऐप मुख्यमंत्री द्वारा अभियंता दिवस पर लोकार्पित किए जाने का प्रस्ताव है। भास्कराचार्य संस्थान द्वारा तैयार मास्टर प्लान रोड मैपिंग टूल पर भी चर्चा हुई, जिसे 1 नवम्बर को मध्यप्रदेश स्थापना दिवस पर लॉन्च करने का लक्ष्य रखा गया है। मंत्री श्री सिंह ने कहा कि इस टूल से सड़क योजना वैज्ञानिक और डेटा आधारित होगी।

नर्मदा परिक्रमा पथ का विकास

बैठक में नर्मदा परिक्रमा पथ पर प्रस्तुतीकरण भी दिया गया। मंत्री श्री सिंह ने कहा कि यह पथ श्रद्धालुओं के लिए केवल एक रास्ता नहीं होगा, बल्कि आस्था और संस्कृति का अनुभव बनेगा। इसमें ठहरने,

भोजन और शौचालय जैसी सुविधाएँ होंगी। घाटों और मंदिरों का जीर्णोद्धार होगा तथा पूरी योजना ईको-फ्रेंडली सिद्धांतों पर आधारित रहेगी। उन्होंने आश्वासन दिया कि संत समुदाय और स्थानीय समाज की राय लेकर ही इस योजना को अंतिम रूप दिया जाएगा।

समीक्षा बैठक में मंत्री श्री सिंह ने कहा कि विभाग की प्राथमिकता पारदर्शिता और जवाबदेही है। उन्होंने कहा कि ÷जनता को हर सड़क और भवन में गुणवत्ता और पारदर्शिता का अनुभव होना चाहिए।

बंटवारे की बही बनाने रिश्वत ले रहा था पटवारी, लोकायुक्त टीम ने रंगे हाथ पकड़ा

जबलपुर। मझौली में पटवारी प्रवीण कुमार पटेल द्वारा बंटवारा की बही बनाने के लिए 6 हजार रुपए की रिश्वत ली जा रही थी। जिसे जबलपुर से पहुंची लोकायुक्त टीम ने रंगे हाथ पकड़ा है। पटवारी उक्त रिश्वत की राशि सिहोरा में पटवारी आफिस में ले रहा था। इस संबंध में लोकायुक्त एसपी अंजुलता पटले ने बताया कि बिशाली पटेल निवासी मझौली द्वारा लोकायुक्त पुलिस अधीक्षक को आवेदन पत्र दिया कि उसकी पैतृक जमीन के बंटवारे के संबंध में मझौली तहसीलदार द्वारा बंटवारे का आदेश किया जा चुका है लेकिन पटवारी प्रवीण पटेल द्वारा बंटवारे को कंप्यूटर एवं बही पर चढऩे के एवज में 6000 रिश्वत की मांग कर रहा है। शिकायत के बाद आज बिशाली पटेल ने पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस के पीछे बिजली ऑफिस के पास अमित गर्ग का मकान सिहोरा में स्थित पटवारी ऑफिस पहुंचकर पटवारी प्रवीण कुमार पटेल को 6 हजार रुपए की रिश्वत दी, तभी लोकायुक्त टीम के राहुल गजभि, उमा कुशवाहा निरीक्षक शशिकला ने दबिश देकर रंगे हाथ पकड़ लिया। पटवारी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 संशोधित 2018 की धारा 7 ए, 13 (1) बी 13(2) के अंतर्गत कार्यवाही की है।

स्वामी प्रकाशक एवं मुद्रक अंकित शर्मा, संपादक शीलू शर्मा द्वारा जवाहर नगर गाली नं. 10 सतना से प्रकाशित तथा अंकित शर्मा द्वारा कोरल ऑफसेट सतना द्वारा मुद्रीत करवाकर प्रकाशित।
समस्त न्याय क्षेत्र सतना होगा। Mail id : udghoshsamay@gmail.com Mob. 7987290705